

हरियाणा विधान सभा

की

कार्यवाही

16 जुलाई, 1974

खंड 2, अंक 7

अधिकृत विवरण

विशय सूची

मंगलवार, 16 जुलाई, 1974

पृष्ठ संख्या

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर	(7) 1
ध्यानाकर्षण प्रस्ताव	(7) 29
कार्य-मंत्रणा समिति का तृतीय प्रतिवेदन	(7) 31
विशेषाधिकार समिति का द्वितीय प्रारम्भिक प्रतिवेदन तथा समय बढ़ाना	(7) 31
औचित्य प्रश्न-दी हरियाणा कैनल एण्ड ड्रेनेज बिल 1973 के सम्बन्ध में	(7) 32
दी हरियाणा कैनल एण्ड ड्रेनेज बिल 1973	(7) 35

हरियाणा विधान सभा

मंगलवार, 16 जुलाई, 1974

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल, विधान भवन, सैक्टर-1, चण्डीगढ़, में 14.00 बजे हुई। अध्यक्ष (चौधरी सरूप सिंह) ने अध्यक्षता की।

तारांकित प्र न एवं उत्तर

Power House in Jind District

***758. Sh. Dhaja Ram:** Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state the names of the places in district Jind, where new Power House Sub-Station are under construction, together with, the time by which the same are likely to start functioning?

State Minister for Irrigation and power(Sardar Harmohinder Singh Chatha): New Power Sub-Station are being Constructed at the following places in district Jind:-

(i)	Safidon	132 K.V. Sub-Station
(ii)	Uchana	132 K.V. Sub-Station
(iii)	Garhi	132 K.V. Sub-Station
(iv)	Kheri	132 K.V. Sub-Station
(v)	Naguran.	132 K.V. Sub-Station

The above Sub-Station are expected to be completed during current financial year i.e. 1974-75, subject to the availability during required equipment. These will start functioning immediately on completion.

Industrial Town

***767. Chaudhri Ram Lal Wadhwa:** Will the Minister for Industries be pleased to state—

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to declare the Karnal town as industrial town; if so, when; and

(b) if the reply to part (a) above be in the negative whether the Government intends to set up an Industrial Colony at Karnal?

Industries Minister (Sh. Harpal Singh):

(a) No. No. Town in the State is declared as Industrial Town.

(b) One Industrial Development Colony is already in existence in Karnal and the proposal for establishing another is under consideration of the Government.

Water Supply Schemes

***783 Sh. Amar Singh:** Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state the approximate date on which the following water supply schemes stated functioning in each case—

1. Jamalpur in Bawani Khera Tehsil;

2. Paposa in Bawani Khera Tehsil;
3. Barsi in Bawani Khera Tehsil; and
4. Umra and Sultanpur in Hansi Tahsil?

गृह तथा स्वास्थ्य राज्य मंत्री (श्रीमती भारदा रानी):

1.	जमालपुर	कार्य 1971-72 में चालू किया गया। कार्य प्रगति में है। कोई निश्चित तिथि कार्य सम्पन्न करने के सम्बन्ध में नहीं बताई जा सकती, यह धनराशि के उपलब्ध होने पर निर्भर है।
2.	पपोसा	यथोपरि
3.	बरसी	पंचायत की ओर से सार्वजनिक भाग तथा वाटर वर्क्स बनाने के लिए भूमि न देने के कारण कार्य चालू नहीं किया गया।
4.	उमरा तथा सुलतानपुर	यथोपरि

श्री अमर सिंह: स्पीकर साहब, जमालपुर और पपोसा की सन् 1971-72 से वही स्थिति बतायी जा रही है। क्या मंत्री महोदया यह बताने का कष्ट करेगी कि कितनी धन-राशि इन

दोनो वाटर स्पलाई स्कीमज पर खर्च करनी है और कितनी अब तक खर्च की जा चुकी है।

श्रीमती भारदा रानी : जमालपुर की स्कीम का ऐस्टीमैंट पांच लाखा और 75 हजार रुपए का है जिसमे से दो लाखप 30 हजार रुपया इसको मिल चुका है। 59 हजार रुपया अभी पंचायत से लेना बाकी है, 20 हजार रुपया पंचायत ने दिया है। एक लाख 91 हजार रुपया खर्च हो चुका है। इस स्कीम पर 33 परसेन्ट काम हो चुका है।

पपोसा की स्थिती यह है कि यह चार गावों की स्कीम है और यह सात लाख 63 हजार रुपए की है। इसमे कोई 4 लाख 70 हजार रुपया अभी तक स्टेट से दिया जा चुका है। इसमे 92 हजार रुपए की बैनिफिसरी भोयर है जो पंचायत ने देना है। 45 हजार रुपया उन्होने दिया है 47 हजार रुपया अभी बाकी है। चार लाख 97 हजार रुपए का काम किया जा चुका है। 65 परसेंट इसका काम खत्म किया जा चुका है।

श्री अमर सिंह: क्या मंत्री महोदया यह बतानवे की कृपा करेगी कि दादरी और लौहरू मे बैनिफिसरी भोयर नही लिया जाता है लेकिन बवानीखेड़ा जो भिवानी डिस्ट्रिक्ट का हिस्सा हैं उससे बैनिफिसरी भोयर लिया जाता है? क्या उसको एग्जैम्पट किया जाएगा?

श्रीमती भारदा रानी: अध्यक्ष महोदय, ऐसी कोई भी स्कीम नहीं है। पिछले दिनों गवर्नमेंट आफ इन्डिया की ऐक्सलरेटिड स्कीम चली थी, कुछ जरूरी सीानों पर चालू की गई थी लेकिन स्टेट गवर्नमेंट की कोई ऐसी स्कीम नहीं है। जिसमे बैनिफिसरी भोयर न लिया जाता हों। हां यह अव य है कि जो बहुत ड्राई एरिया है जहां पर बहुत ही कहत ही हालत होती है वहां ड्राउट रिलीफ के अन्डर उनका बैनिफिसरी भोयर गवर्नमेंट की और अदा कर दिया जाता है।

श्री अमर सिंह: क्या मंत्री महोदया के नोटिस मे यह है कि बवानीखेड़ा तहसील के बहुत से गांव बिल्कूल लोहारू जैसे ही है और यह इलका बारि 1 पर ही निर्भर करता है, इन गावों को इस बैनिफिसरी भोयर से एग्जेम्पट कर दिया जाएगा?

श्रीमती भारदा रानी: अध्यक्ष महोदय, यह रिपोर्ट तो वहां के हालात के अनुसार मिलती हैं। वहां से इस प्रकार की रिपोर्ट यदि कोई मिली भी होगी तो हमारे नोटिस मे नहीं है। उनका ड्राउट एरिया मे भामिल नहीं किया गया। अगर किया जाता तो उनका बैनिफिसरी भोयर माफ किया जा सकता था।

Doctors working on Adhoc basis

***760 Chaudhri Shiv Ram Verma:** Will the minister for Industries be pleased to state the total number of doctors working on ad-hoc basis in the State at present who have not

been paid their emoluments together with the period of Non-Payment?

गृह तथा स्वास्थ्य राज्य मंत्री (श्रीमती भारदा रानी):

ऐसे डाक्टरों के सम्बन्ध में रिश्ती इस प्रकार है:—

डाक्टरों की संख्या	जिस तिथी के पचात् वेतन नहीं दिया गया
(1) स्वास्थ्य निदेशालय	
1	28.02.1974
40	31.03.1974
6	30.04.1974
(2) मैडीकल कालेज रोहतक	
26	01.04.1974

चौधरी विठ्ठल राम वर्मा: क्या मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेगी कि इतने दिनों से इन डाक्टरों को तन्खाह क्यों नहीं मिली?

श्रीमती भारदा रानी: अध्यक्ष महोदय, ऐसा है कि ये सब ऐडहोक अफ्वायंटी है। पब्लिक सर्विस कमीशन को रिक्यूजीशन

भेजी गई थी, इसके बाद 01.03.1971 को रिक्‍यूजी ान आ गई, क्योंकि रिक्‍यूजी ान भेजी गयी थी, इनकी अनुमति हमारे पास रैगुलर कैंडीडेटस पब्लिक सर्विस कमी न से आ जायेगा लेकिन उस समय तक नही आये । इसके बाद उनको लिखा गया आरैर ए. जी. साहब से भी इनके सब केसिज कलियर होने की वाले या हो भी गये हो, उनके पास भायद पे—स्लिप भेज दी गई हो या भेजी जा रही होगी ।

चौधरी ि ाव राम वर्मा: क्या मंत्री महोदया बतायेगी कि किस तारीख तक इनकी सारी तंखाह दे दी जायेगी?

श्रीमती भारदा रानी: अध्यक्ष महोदय, मैने कहा कि भायद ए.जी. के जरिए, पे—स्लिप भेजी ही जा रही है, फाईनेलाईज के करीब ही है । यह हमारी रिसैन्ट इनफर्मे ान है ।

ताराकिंत प्र न संख्या 789

यह प्र न पूछा नही गया क्योंकि माननीय सदस्य उस सदन मे उपस्थित नही थे ।

***823 Malik Sat Ram Dass Batra:** Will the Minister for Irrigation Government to utilise the water of Ghagger;

(a) whether there is any schemei under consideration of the Government to utilise the water of Ghagger;

(b) if so, whether any investigations were carried out in this behalf;

(c) if so, the details thereof; and

(d) the areas which are likely to be benefited by this scheme?

Stat Minister for Irrigation and Power (Sardar Harmohinder Singh Chatha):

(a) Yes.

(b) Investigations on two scheme have already been complted and investigation on two more schemes are in progrss.

(c) Details of schemes already investigated are as under:-

1. Scheme for Ghaggar Water into tail Ratia Branch

(i)	Cost of the Scheme	Rs.2178,000/-
(ii)	Supplies proposed to be pumped.	221 Cusecs
(iii)	Number of days for which supplies would be pumped	50 Days
(iv)	No. of pump Houses	1
(v)	Total Lift.	23.39 ft.

2. Lifting Ghggar Water into tail Rodi Branch

(i)	Cost	24,72,000
(ii)	Supplies proposed to be pumped.	166 Cusecs
(iii)	Number of days for which supplies would be pumped	59 Days
(iv)	No. of pump Houses	1
(v)	Total Lift.	16.85 ft.

मलिक सतराम दास बतरा: क्या मंत्री महोदय यह बतायेगे कि यह गवर्नमेंट के विचाराधीन बात है हर 8-10 मील के फासले पर रेगूलैटर लगा कर डायरेक्ट माईनर निकाल दी जाये ताकि ये लिफ्ट स्कीम अन-इकोनिमिकल न हो क्योंकि पानी भी थोड़ा है?

सरदार हरमोहिन्द्र सिंह चट्ठा: स्पीकर साहब, इस बात को हमने एग्जामिन किया था लेकिन तरीका ठीक समझा गया जो अर्ज किया है।

चौधरी िाव राम वर्मा: क्या मंत्री महोदय बतायेगे कि जैसे उन्होंने अभी घग्गर की स्कीम बनायी है, क्या मारकंडा और टांगरी की भी कोई ऐसी स्कीम है?

सरदार हरमोहिन्द्र सिंह चट्ठा: टांगरी की स्कीम इनवैस्टीगे ान की जा रही है। टांगरी का पानी लिफ्ट करके नरवाना ब्रान्च में डाला जायेगा।

चौधरी विठ्ठल राम वर्मा: क्या घग्गर का पानी जो इस्तेमाल किया जा रहा है इसमें करनाल और कुरुक्षेत्र जिले को भी पानी मिलेगा?

सरदार हरमोहिन्द्र सिंह चट्ठा: जितना पानी हम पम्प करते हैं वह पानी इस सिस्टम में डाल देते हैं। यह पानी किसी पार्टिकूलर एरिया के लिए नहीं होता। उस एरिया का वहां से पानी दे दिया जायेगा, पिछले एरिया का वहां से काट लिया जायेगा। यह सारा सिस्टम पानी का है।

मलिक सतराम दास बतरा: क्या मंत्री महोदय यह बताने का कष्ट करेंगे कि मैक्सिमम फलड हर वर्ष कितना मापा जाता है और उसकी यूटेलाइजे टन कितनी हैं।

सरदार हरमोहिन्द्र सिंह चट्ठा: मैक्सिमम फलड 23-24 हजार क्युसिक आज तक आया हैं। इसको यूटेलाइजे टन सिर्फ 25 परसेंट हुई है।

श्री जगजीत सिंह टिक्का: क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि घग्गर के ऊपर चंडी-मंदिर के पास एक डेम बनाने की जो स्कीम थी, उसको कब तक बनाने का सरकार का विचार है?

सरदार हरमोहिन्द्र सिंह चट्ठा: स्पीकर साहब, मैंने पिछले सेशन में भी अर्ज किया था कि यह स्कीम जरूर है लेकिन इसकी प्रायोरिटी बहुत लो है।

राव अभय सिंह: क्या मंत्री महोदय यह बतायेगे कि साहबी नदी पर बांध बनान की जो स्कीम चल रही है, उस पर कम तक काम भुरू हो जायेगा?

सरदार हरमोहिन्द्र सिंह चट्ठा: इसके लिये तो सैपरेट नोटिस की जरूरत है।

चौधरी पीर सिंह: क्या मंत्री महोदय, यह बताने की कृपा करेगेंकि जो घग्गर नदी हिसार के एरिया से गुजरती है, वह हिसार के जिले के कितने एरियें का सैराब करती है?

सरदार हरमोहिन्द्र सिंह चट्ठा: घग्गर नदी कितने एरिया को सैराब करती है, इसके बारे मे मुख्य मंत्री साहब और मंत्री साहब ने भी यह अर्ज किया था कि यह कोि । । की जाती है कि फलड वाटर और अन्डरग्राउन्ड वाटर को मैक्सिमम टेप करके मैक्सिमम पानी दिया जायें।

ताराकित प्र न संख्या 835

यह प्र न पूछा नही गया कयेांकि माननीय सदस्य उस सदन मे उपस्थित नही थें।

***819 Chaudhri Mehar Chand:** Will the Minister for Finance be pleased to state the amount of expenditure incurred by the State Government on pay and allowances on staff of all the Haryana Government Department during the financial year 1967-68 and 1973-74 separately?

Finance Minister(Sh. Ram Saran Chand Mittal):

The Total wage bill of Haryana Government employees on account of basic pay, dearness pay, dearness allowance during the year 1967-68 was about Rs. 2,669 lakhs. Information relating to the year 1973-74 is still being collected, and sufficient time will be required to compile it. This information when collected and compiled will be supplied to the Secretary Haryana Vidhan Sabha for Transmission to the Honorable Member.

चौधरी राम लाल वधवा: क्या मंत्री महोदय यह बतलाने की कृपा करेंगे कि यह खर्च टोटल रैवेन्यू का कितना परसेंट बनता है।

श्री राम सरन चन्द मित्तल: यह तो आपको टोटल रैवेन्यू से हिसाब लगाकर कैलकुलेट करना पड़ेगा।

चौधरी मनफूल सिंह: क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि इसमें आई.ए.एस. और एच.सी.एस. आफिसर्स का पे—एण्ड—अलाउंसिज कितना है और बाकी का कितना है?

श्री राम सरन चन्द मित्तल: इसकी ब्रेक—अप तो एक अलग बात है। इसके अन्दर ऐक्सपेंडीचर आन हाउस रेंट अलाउन्स, कम्पनसेटरी अलाउन्स एण्ड मैडीकल री—इम्बर—समैटस भामिल नहीं है। बाकी सब खर्चा इसमें भामिल है। मेरे पास वह ब्रेक—अप नहीं है यह ब्रेक—अप मेरे पास है। बेसिक पे 14 करोड़,

50 लाख 19 हजार, डियरनैस—पे 3 करोड़ 22 हजार और डियरनैस अलाउन्स 9 करोड़ 18 लाख 91 हजार हैं।

श्री के.एन. गुलाटी: क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि एक टेम्पोरेरी ऐम्पलाई को कितने परियुक्त बाद परमानेंट कर दिया जाता है?

श्री राम सरन चन्द मित्तल: इसका इस सवाल के सम्बन्ध नहीं है।

श्री अमर सिंह: क्या मंत्री महोदय यह बताएंगे कि 1967-68 में क्लास थ्री और क्लास फोर के ऐम्पलाईज के पे—एण्ड—अलाउन्सिज पर कितना खर्चा किया है और क्लास टू और क्लास वन के आफिसरज पर कितना खर्च किया है?

श्री राम सरन चन्द मित्तल: इस ब्रेक—अप के लिये तो अलग से नोटिस देना पड़ेगा।

श्री पीर चन्द: क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि आजकल की मंहगाई को देखते हुए सरकार सभी डिपार्टमेंट्स के मुलाजिमों का कुछ और मंहगाई भत्ता बढ़ायेगी?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

Primary School

***855 Sh. Bihari Lal Balmiki:** Will the Minister for Education be pleased to state—

(a) the district-wise total number of village in the State in which Primary Schools existed as on 1st May, 1969 and as on 31st March, 1974, Separately; and

(b) the district wise number of villages in the State in which the Government intends to open primary School by the end of the financial year 1974-75?

शिक्षा तथा परिवहन राज्य मंत्री (श्रीमती प्रसन्नी देवी):

(क) एक सूची सदन की मेज पर रखी जाती है।

(ख) भून्य।

सूची

जिलावार गांवों की सख्या, जिसमे प्राईमरी स्कूल/कक्षायें उपलब्ध है।

क्रमां क	जिले नाम	का 01.05.69 को उन गांवों की संख्या जहां प्राईमरी स्कूल/कक्षायें उपलब्ध हैं।	31.03.74 को उन गांवों की संख्या जहां प्राईमरी स्कूल/कक्षायें उपलब्ध हैं।
(1)	अम्बाला	748	1089
(2)	गुड़गांव	1038	982

(3)	हिसार	999	766
(4)	जीन्द	255	337
(5)	करनाल	1199	523
(6)	महेन्द्रगढ़	497	669
(7)	रोहतक	743	440
(8)	सोनीपत	--	322
(9)	भिवानी	--	454
(10)	कुरुक्षेत्र	--	700
टोटल		5479	6282

नोट:- उपरोक्त आंकड़ों में ऐसे ग्रामों की संख्या भी शामिल है जिन ग्रामों में प्राथमिक शिक्षा की सुविधाएँ 1 से 1.6 किलोमीटर के अन्दर अन्दर प्राप्त हैं।

चौधरी फूल सिंह मोलाना: क्या मंत्री महोदया यह बतायेगी कि राज्य में कुल कितने ऐसे गांव हैं जिनमें प्राइमरी स्कूल नहीं है?

श्री मती प्रसन्नी देवी: 449 ऐसे गांव हैं जहां पर प्राइमरी स्कूल नहीं है।

चौधरी दल सिंह: क्या मंत्री महोदया यह बताने कि कृपा करेगी कि साल 1974-75 में सरकार हरियाणा प्रान्त में और कितने प्राइमरी स्कूल खोलने जा रही है?

श्रीमती प्रसन्नी देवी: कोई नहीं।

चौधरी दल सिंह: क्या मंत्री महोदया यह बतायेगी कि इसका कारण क्या है?

श्रीमती प्रसन्नी देवी: इसलिए कि इसकी कोई खास जरूरत नहीं है। अब भी जो गांव बाकी है जिनमें प्राइमरी स्कूल नहीं है, उनके बिल्कूल पास के गांव में स्कूल है और उनका कोई बहुत बड़ा फासला नहीं है। इसके अलावा पैसों की कमी वाली बात भी है।

श्री गुलाब सिंह जैन: क्या मंत्री महोदया यह बताएंगी कि इन 449 गांवों के अन्दर प्राइमरी स्कूल क्यों नहीं हैं।

श्रीमती प्रसन्नी देवी: इसलिये नहीं है क्योंकि वहां पर इसकी कोई जरूरत महसूस नहीं की गयी। जहां जहां पर जरूरत महसूस की गयी वहां वहां पर प्राइमरी स्कूल खोले हुए हैं।

श्री अमर सिंह: मंत्री महोदया ने यह फरमाया है कि 449 में प्राइमरी स्कूल नहीं है तो क्या मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेगी कि वहां पर कम्पलसरी एजुकेशन की कन्डीशन

फुलफिल हो रही है? अगर नहीं हो रही है तो यह उल्लघोन क्यों हो रहा है?

श्रीमती प्रसन्नी देवी: जैसे कि मैंने अभी बताया है ये गांव ऐसे है जिनके बिल्कूल पास ही के गांव मे स्कूल है। इनमे से हमारा कोई भी ऐसा गांव नहीं है जिसका फासला 1.6 किलोमीटर से ज्यादा हो जहां पर कि स्कूल है या ये वो गांव है जो बहुत छोटे है ओर बच्चों की इतनी तादाद ही नहीं हो सकती कि हम अलग से स्कूल चला सकें।

चौधरी िव राम वर्मा : क्या मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेगी कि इन्द्री की कांस्टीच्यूएंसी मे कितने ऐसे गांव है जिनमें प्राइमरी स्कूल नहीं है?

श्रीमती प्रसन्नी देवी: इसके लिए तो अलग से नोटिस देना पड़ेगा।

चौधरी मेहर चन्द: क्या मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेगी कि जो प्राइमरी स्कूल स्टेट मे ऐगजीस्ट करते है, उनमे से लड़यिों के स्कूल कितने है?

श्रीमती प्रसन्नी देवी: इसके लिये भी अगलग से नोटिस देना पड़ेगा।

राव बंसी सिंह: क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि डिस्ट्रिक्ट महेन्द्रगढ़ के अन्दर ऐसे कितने गांव हैं जहां पर प्राइमरी स्कूल नहीं है?

शिक्षा मंत्री (श्री माडू सिंह मलिक): डिस्ट्रिक्ट महेन्द्रगढ़ में ऐसे 23 गांव हैं।

चौधरी दल सिंह: स्पीकर साहब, मंत्री महोदय ने अपने जवाब में यह बताया था कि जहां पर स्कूल नहीं है, उनके आस-पास स्कूल है, इसलिए वहां पर नहीं खोले गये हैं। मंत्री महोदय यह फरमायेगी कि क्या इसका मतलब यह है कि आप का उन गांवों के अन्दर स्कूल खोलने का इरादा नहीं है? अगर इरादा है तो कब तक खोल देंगे?

श्रीमती प्रसन्नी देवी: स्कूल तो सब जगह देंगे लेकिन सवाल यह है कि यदि 1.6 किलोमीटर पर स्कूल है जो सभी बच्चे वहां पर जा सकते हैं। अगर जरूरत होगी तो बाद में वहां पर भी स्कूल खोले देंगे।

चौधरी पीर चन्द: क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि उन्होंने जो 449 गांव ऐसे बताये हैं जहां पर स्कूल नहीं है, वे कौन-कौन से जिले में 43, हिसार में 38, भिवानी 17, रोहतक में 3, सोनीपत में 7, गुड़गांव में 142, जींछ में 18 और नारनौल में 23

चौधरी फूल सिंह कटारिया: क्या मंत्री महोदया यह बतायेगी कि इस बात के मद्देनजर कि छोटे छोटे बच्चों को धूप में आना जाना पड़ता है, क्या वे यह महसूस नहीं करती कि बच्चे एक मील कैसे जाते हैं जबकि आजकल एक फर्लांग भी चलकर कोई राजी नहीं है?

श्रीमती प्रसन्नी देवी: एक मीलप नहीं, एक किलोमीटर कुछ प्वायंट फासला है। यह मील से भी कम फासला है।

श्री के.एन.गुलाटी: जैसे कि मिनिस्टर साहब ने अभी फिगरज दी है।, उसमें गुड़गांवां के सबसे ज्यादा गांव है जहां पर प्राइमरपी स्कूल नहीं है, गुड़गांवा डिस्ट्रिक्ट के साथ यह बेइन्साफी क्यों है? (व्यवधान एवं भाोर)

श्री माडू सिंह मलिक: बेइन्साफी वाली तो कोई बात नहीं है।

Bus service From Jhajjar to Chandigarh

***893 Chaudhri Phul Singh Kataria:** Will the minister for Develpment be pleased to state—

(a) whether it is a fact that Bus Sevice from Jhajjar to Chandigarh via Sonapat has been stopped; if so, the reasons therefor; and

(b) whether there is any prosoal under consideration of teh Government to resatart the same Bus Sevice from Jhajjar to Chandigarh via Digal, Rohtak and Gohana?

शिक्षा तथा परिवहन राज्य मंत्री (श्रीमती प्रसन्नी देवी):

(क) एक बस सेवा झज्जर से चण्डीगढ़ के लिए वरास्ता सोनीपत चार मास के लिए तजुर्बे के तौर पर चलाई गई थी। इसे घाटे पर चलने के कारण बन्द कर दिया गया।

(ख) जी, नहीं।

चौधरी फूल सिंह कटारिया: क्या मंत्री महोदया यह बताने की कृपा करेगी कि चण्डीगढ़ से हरेक सब-डिविजन के भाम के वक्त जबकि गाड़ी चलती है तो झज्जर पर को क्यों नहीं चलती?

श्रीमती प्रसन्नी देवी: झज्जर से होकर दो-तीन बसें जाती है। एक चण्डीगढ़ से रिवाड़ी वाया झज्जर जाती है एक चण्डीगढ़ से पुनहाना वाया झज्जर जाती है। इसलिये इसकी जरूरत नहीं समझी गयी कि अगल से इसके लिये गाड़ी चलाई जायें।

चौधरी दल सिंह: मिनिस्टर साहिबा ने कहा कि घाटा रहा है। मैं उनसे यह पुछना चाहता हूं कि चार महीनें मे कितना घाटा रहा है।

श्रीमती प्रसन्नी देवी: अगस्त के महीने मे एक रूपया पांच पैसे प्रति-किलोमीटर आमदनी हुई और एक रूपया सतर पैसे खर्च हुआ। इसी तरह से सितम्बर के महीने मे आमदनी 80 पैसे

प्रति किलोमीटर हुई और एक रूपया बाईस पैसे खर्चा हुआ। अक्टुबर के महीने में 90 पैसे प्रति किलोमीटर इन्कम हुई और एक रूपया 26 पैसे प्रति किलोमीटर खर्चा हुआ है। इसी ढंग से नवम्बर में 90 पैसे प्रति किलोमीटर इन्क हुई और एक रूपया 27 पैसे खर्चा हुआ।

चौधरी मनफूल सिंह: स्पीकर साहब, मंत्री महोदया ने फरमाया कि तीन बसें चलती हैं। झज्जर से सुबह 10.40 बजे चलती है और 6.30 बजे पहुंचती है। इसके बाद कोई बस नहीं चलती।

विकास मंत्री (कर्नल महा सिंह): स्पीकर साहब, झज्जर से तीन बसें रिवाड़ी नारनोल होती हुई हैं और एक पुनहाना से चण्डीगढ़ आती है। बसें बहुत चलती हैं। स्पीकर साहब, इस बारे में माननीय सदस्य तथा कटारिया साहब ने मेरे से कहा था। मैं इसके बारे में बता दूँ कि अभी एक बस रोहतक से झज्जर तक इनकी सुविधा के लिए एक्सेटेड कर रहे हैं जो कि वहां भाम को पहुंचेगी और सुबह झज्जर से चला करेगी यहां दोपहर का पहुंच जाया करेगी।

राव अभय सिंह: क्या मिनिस्टर साहब बताने की कृपा करेंगे कि सरकार की कोई ऐसी स्कीम है कि हर जिला हैड क्वार्टर को चण्डीगढ़ से डिलेक्स बस से मिला दिया जाए?

कर्नल महा सिंह: अभी तो नहीं है।

चौधरी रामप लाल वधवा: क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि बस सर्विस चलाने के लिए पब्लिक की तकलीफ को अहमियत दी जाती है या पैसे को?

कर्मल महा सिंह: पब्लिक की तकलीफ को और सदस्यों की तकलीफ को ख्याल में रखते हैं।

मलिक सतराम दास बतरा: क्या मिनिस्टर साहब, बताने की कृपा करेंगी कि क्या कभी इस बात का अन्दाजा लगाया गया कि कितनी ऐसी बसें हैं जो रोड पर जाती हैं और फिर पांच-छः महीने के बाद खड़ी हो जाती हैं?

श्रीमती प्रसन्नी देवी: इसके लिए सैपरेट नोटिस चाहिए।

Haryana Raodways

***914 Sh. Siri Kishan Dass:** Will the Minister for developoment be pleasd to state—

(a) the per mile return of the buses of the Haryana Roadways in the year 1968 and 1974, Saparately;

(b) the averange breakdowns which took place in the Years 1968 and 1974] saparatly;

(c) the total number of technically qulified supervisory staff in the Raodways workshops at present with thier qualification; and

(d) the procedure adopted for the recruitment of the said staff in the workshop?

शिक्षा तथा परिवहन राज्य मंत्री (श्रीमती प्रसन्नी देवी):

(ए)	वर्ष	हरियाणा राज्य परिवहन की बसों के प्रति मील रिटर्न (पैसे में)
	1967-68	29.8
	1973-74	6.7

(बी) 1967-68 में कुल ब्रेक-डाउन की संख्या 883 थी और 1973-74 में यह संख्या 1288 थी।

(सी) 6 कर्मचारी प्रबन्धक, 3 मैकेनिकल डीगरी होल्डर्स तथा 3 डिप्लोमा होल्डर्स।

(डी) 2 कर्मचारी प्रबन्धकों की पदोन्नति की गई और भोश 4 को तदर्थ आधार पर लगाया गया है।

चौधरी दल सिंह: मंत्री महोदय ने बताया है कि 1967-68 में 883 ब्रेक डाउन थी और 1973-74 में 1288 ब्रेक डाउन थी। यह इन्क्रीज किस लिए हुई?

श्रीमती प्रसन्नी देवी: स्पीकर साहब, उस वक्त बसें बहुत थोड़ी थीं। उस वक्त 567 बसें थीं और अब ये बढ़कर 1537 हो गई हैं। इसी तरह से बसों की तादाद बढ़ने के साथ-साथ ब्रेक

डाउन्ज की तादाद भी बढ़ेगी लेकिन पहले के मुकाबल में ब्रेक डाउन्ज की तादाद घट रही है।

चौधरी फूल सिंह कटारिया: क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि ये ब्रेक—डाउन्ज कौन से डिपों से ज्यादा है?

श्रीमती प्रसन्नी देवी: इसके लिए अलग से नोटिस चाहिए।

Demand and Distribution of Chemical Fertilizers

***918 Chaudhri Ram Parshad:** Will the Minister for Agriculture be pleased to state—

(a) the total number of manure pits, if any, dug up before the onset of monsoon at various places in the State;

(b) the total quantity of manure available in the State at present.

(c) the total demand of chemical Fertilizers in the State at present; and

(d) the total quantity that will be made available for distribution through various agencies.

कृषि मंत्री (चौधरी भजन लाल):

(क) जिला हिसार, भिवानी, महेन्द्रगढ़, करनाल, कुरुक्षेत्र, सोनीपत तथा रोहतक में 23,067 देसी खाद के गढ़े खोदे गये। और जिलों से रिपोर्ट बानी बाकी है।

(ख) राज्य में उपलब्ध देसी खाद की मात्रा से सम्बन्धित सूचना प्राप्य नहीं हैं।

(ग) साधारण रासायनिक खाद के रूप में जहाँ खरीफ 1974 के लिए हमारी मांग 4,02,083 टन है, वहाँ रबी 1974-75 के लिए यह मात्रा 6,68,750 टन है और इस प्रकार कुल मांग 10,70,833 टन बैठती है।

(घ) साधारण खाद के रूप में खीफ 1974 के लिए, सहकारी तथा निजी एजेंसियों के माध्यम से वितरित करने हेतु 2,80,497 टन खाद अलाट किया गया है परन्तु रबी 1974-75 के लिए भारत सरकार ने कोई अलाटमेंट अभी तक नहीं की।

चौधरी दल सिंह: स्पीकर साहब, मंत्री महोदय ने अभी बताया है कि 10 लाख टन खाद की कमी हरियाणा में है। क्या मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इस कमी को मीट करने के लिए आप क्या उपाय कर रहे हैं, क्या सरकार इस कमी को पूरा करे सकेगी या नहीं?

चौधरी भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, भायद आनरेबल सदस्य ने सुना नहीं है। मैंने कहा था कि दस लाख टन की मांग है, डिमान्ड है, मैंने यह नहीं कहा कि दस लाख टन की कमी है। सवाल जवाब में मैंने बताया है कि खरीफ की फसल के लिए हमारी मांग 4 लाख टन है और भारत सरकार ने डेढ़ लाख टन खाद दे दी है। 1974-75 की रबी के लिए यह मांग 6 लाख 68

हजार 750 टन है। इस तरह से यह मांग 10 लाख टन हो जाती है।

राव बंसी सिंह: क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि महेन्द्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में कितने खाद के गढ़े खोदे गए हैं और कितने और खोदने हैं?

चौधरी भज लाल: महेन्द्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में 3 हजार 91 गढ़े खोदे गए हैं।

चौधरी राम प्रसाद: क्या मंत्री महोदय इन गढ़ों की जिलेवा संख्या बताने की कृपा करेंगे?

चौधरी भजन लाल:

हिसार	5137
भिवानी	1038
महेन्द्रगढ़	3091
करनाल	1016
कुरुक्षेत्र	557
सोनीपत	7279
रोहतक	4953

चौधरी मेहर चन्द: अध्यक्ष महोदय पार्ट ए के जवाब मे बताया गया है कि मेन्योर पिटस खोदे गए। क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेगे कि उनमे कितना रिफ्यूज डाला गया और उनमे खाद की कितनी क्वांटिटी तैयार होगी?

चौधरी भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, यह देसी खाद की बात है यह दूसरे खाद की बात नहीं है। गोबर जो है उसका कोई वजन नहीं किया जाता कि कितनी मात्रा में है कितना परसेन्ट वह पड़ा जो दे ि खाद होती है उसमे वजन का सवाल नहीं होता।

चौधरी मेहर चन्द: अगर वजन का सवाल नहीं तो क्या मंत्री महोदय बतायेगे कि कितने गढे है जिनमें रिफ्यूज डाला गया और कितने गढे खाद तैयार होगा?

चौधरी भजन लाल: टोटल गढे जो खोदे गए है 23,067।

चौधरी दल सिंह: पार्ट ए के जवाब मे बताया है कि 23,067 गढे खोदे गए क्या मंत्री महोदय बतायेगे कि इस इन्फरमै ान का आधार क्या है। यह इन्फरमै ान कहां से मिली?

मुख्य मंत्री(चौधरी भजन लाल): इस सूचना का आधार है कि हमारी खातिर ये गढे खोदे जाए और हम इनकी खातिर गढे खोदे जाए।

श्री गौरी भांकर: क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि जिला जीन्द की जो सूचना नहीं आई इसका कारण यह तो नहीं कि वहां काम न भुरू किया गया हो, वहां कोई गड्ढे वगैरह न खोदे गए हो?

चौधरी भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, ऐसी बात नहीं है। हर जिले में डिप्टी कमिश्नर की चेयरमैनशिप में एक कमेटी बनी हुई है। बी.डी.प्रोज. के जिम्मे यह काम है और सारे आफिसर्स की मिटिंग बुलाई जाती है। हर जिले में काम स्टार्ट किया हुआ है। अभी दो-तीन जिलों की फिगरज नहीं आई है जब वे आ जाएगी तो आनरेबल मैम्बर को वे फिगरज भिजवा देंगे।

चौधरी शिव राम वर्मा: मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि जा गड्ढे खोदे गए हैं उनका साइज क्या है और उनमें कितना खाद तैयार हो सकेगा?

चौधरी भजन लाल: स्पीकर साहब, जहां तक लम्बाई और गहराई का ताल्लूक है तीन फीट से साढ़े तीन फीट तक गहरे हैं। छः से आठ फीट चौड़ाई और 15 से 21 फीट लम्बाई है लेकिन खाद का वजन बताना कठिन है।

चौधरी पीर चन्द: क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि जो जमींदार खाद के लिए गड्ढे खोदता है उसको सरकार ग्रान्ट देती है अगर नहीं तो ग्रान्ट देने की कोई स्कीम विचाराधीन है?

चौधरी भजन लाल: गड्ढे खोदने के लिए ग्रांट देने की कोई बात नहीं है। अलबत्ता गोबर गैस प्लांट अगर कोई लगाना चाहे तो उसके लिए सरकार लोन देती है और सबसिडी भी देती है।

चौधरी मनफूल सिंह: स्पीकर साहब, फर्मीलाइजर की कीमत दुगनी होने के लिए किसान खाद कम प्रयोग करेगा और इस वजह से अनाज कम पैदा होगा। क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि खाद पर किसान को सबसिडी देने का सरकार को कोई विचार है?

चौधरी भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, जहां तक खाद के रेट का ताल्लूक है, इसमें कोई भाक नहीं कि कीमत काफी बढ़ी है और हमने भारत सरकार से इसके लिए कहा है कि वह सबसिडी दे लेकिन सबसिडी के लिए वे नहीं मान रहे हैं। अब हमने सैन्ट्रल गवर्नमेंट को कहा है कि वह किसानों जो खाद महंग भाव से खरीदकर डालनी पड़ती है, उसका घाटा मीट हो सके।

चौधरी दल सिंह: मंत्री महोदय ने फरमाया कि सैन्ट्रल गवर्नमेंट ने सबसिडी की डिमान्ड रिजैक्ट कर दी है। क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि खाद की कीमत बहुत बढ़ गई हैं, इस बात को ध्यान में रखते हुए हरियाणा सरकार किसान को सबसिडी देने के लिए तैयार है और अगर देने के लिए तैयार है तो क्या सबसिडी है?

चौधरी भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, ऐसी कोई स्कीम सरकार के विचाराधीन नहीं है।

चौधरी विठ्ठल राम भार्गव: अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मंत्री महोदय ने अभी बताया कि ऐसी कोई स्कीम सरकार के विचाराधीन नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है, अगर सरकार यह सब-सिडी किसानों को न देगी तो इससे किसान लोग खाद को कम इस्तेमाल करेंगे और अगर खाद कम इस्तेमाल की जाएगी तो उससे अनाज की पैदावार भी होगी और उस वक्त जो समस्या आपके सामने आएगी उनको विचार में रखते हुए क्या सरकार किसानों को सस्ते भाव पर ज्यादा से ज्यादा खाद देने की कोशिश करेगी?

चौधरी भजन लाल: स्पीकर साहब, जैसा कि मैंने पहले बताया है कि खाद अगर मंहगे भाव का डालना पड़ेगा तो उससे किसानों का अनाज का भाव भी मंहगा मिलेगा इससे किसान को उसके अनाज की कीमत थोड़ी सी ज्यादा बढ़ के मिल जाएगी तो उस में क्या फर्क पड़ेगा। खाद की लागत में कोई अन्तर नहीं आएगा। जब किसान यह महसूस करेगा कि तेरे को 400 रूपए एकड़ का खाद डालना पड़ेगा उसमें 100 रूपये कट्टे की कीमत बढ़ने से या 200 रूपये कट्टे की कीमत बढ़ने से जितना फर्क पड़ता है उतना भारत सरकार उसका भाव बढ़ा होगी, उसमें किसानों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा।

श्री गौरी भांकर: अध्यक्ष महोदय, क्या सरकार कोई ऐसी बात पर विचार कर रही है कि यह जो गोबर है, उसको गड्ढो में डलवाने का प्रबन्ध किया जा सके ताकि इससे ज्यादा से ज्यादा खाद पैदा हो सके और इसके साथ साथ लोगों को गोस पाथने से रोकने का कोई कानून बनाने पर भी विचार कर रही है?

चौधरी भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, ऐसा कोई कानून बनाने की तो बात ही नहीं है लेकिन किसानों को यह बात जरूर कहेंगे कि वे देसी खाद ज्यादा से ज्यादा बनाकर गोबर गैस प्लाट लगा करके देसी खाद का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें।

श्री अमर सिंह: अध्यक्ष महोदय, अभी मिनिस्टर महोदय ने डिस्ट्रिक्ट-वाइज गड्ढों के आकड़ें बताये हैं। क्या उनके पास कोई ऐसी रिपोर्ट भी आई है कि बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में गड्ढे तो खोद दिये गये हैं पर उनमें खाद डाली गई है?

चौधरी भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, ऐसी कोई रिपोर्ट हमारे पास तो नहीं आई कि गड्ढो में खाद ही न डाली जाए। हो सकता है कि आनरेबल मैम्बर के लिए नोटिस में कोठ ऐसी बात हो तो वे सरकार के नोटिस में लाएं हम इसके लिए पूरी कोशिश करेंगे। वैसे यह बात तो किसानों के अपने हित में ही है। किसान खुद हर बात को देखता है, सोचता है और करता है।

चौधरी राम लाल डागर: क्या मिनिस्टर साहब बतनाले की कृपा करेगे कि खाद की मंहगाई की वजह से किसानों को निरा ा है?

चौधरी भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, इस के बारे मे मै पहले ही बता चूका हूं कि इसमे निरा ा होने की कोई बात नही है। जहां खाद के भाव बढे है उसके साथ साथ ही भारत सरकार अनाज के भाव भी बढाने पर विचार कर रही है।

चौधरी िाव राम वर्मा: अध्यक्ष महोदय, क्या मंत्री महोदय यह बतलाने की कृपा करैंगे कि किसानो को खाद इस्तेमाल करने के लिए, उनको प्रोत्साहित करने के सिलसिले मे, क्या सरकार बहुत ही जल्द अनाज के भाव ऐलान करने का विचार रखती है?

चौधरी भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, हमने भारत सरकार को लिखकर भी भेजा है। अभी हाल ही मे एक मीटिंग भीहुई थी। श्री सुब्राह्मनयम परसां चण्डीगढ़ भी आए थे उनके सामने भी हमने कई सम्स्याएं रखी थी कि पैडी की सोईंग भारु है अतः खरीफ की फसल की प्रोक्योरमेंट प्राइस अनाउंस करनी चाहिये ताकि उससे किसानों को पता चल सके कि उसकी पैडी किस भाव पर बिकेगी और मुझे पूरी उम्मीद है कि भारत सरकार बहुत जल्द ही भाव अनाउंस करने वाली हैं।

चौधरी पीर चन्द: अध्यक्ष महोदय, अनाज की बढ़ती हुई कीमत पर सरकार का ध्यान है। क्या हरिजनों और गरीब आदमीयों, जिन का रोजगार भी कम हो गया है, उन्हें कोई सबसीडी देकर या उनके कलए कोइ नये डिपोज खोलकर उन्हें सस्ते दामो पर खाद दिलवाने की सरकार कोि । । करेगी?

चौधरी भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, यहा पर डिपोज का सवाल नही है, खाद की बात है और खाद जितना भी आता है वह को-ओप्रटिव सोसाइप्रेटीज की मारफत बिकता है, प्राइवेट लोगा को सरकार ही नही है।

चौधरी फूल सिंह कटारिया: अध्यक्ष महोदय, जैसे इन्होने कहा कि अनाज का भाव तो तेज हो जाएगा और जमींदारों की यह ख्वाहि । भी है कि भाव तेज हों लेकिन सके साथ साथ क्या गरीब जनता का भी सरकार ख्याल रखेगी कि उन को अनाज ज्यादा मंहगा न दिया जाए?

चौधरी भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, इस सवाल का इससे कोई सम्बन्ध नही लेकिन मै फिर भी बता सकता हूं कि भारत सरकार हर बात का ध्यान रखती है पैदा वाले का भी ध्यानप रखती है और खाने वाले का भी ध्यान रखती है।

चौधरी प्रताप सिंह दौलता: स्पीकर साहब, क्या वजीर साहब यह बताऐगे कि जब यह हरिजन बच्चे पैदा करते है तो गेंहू पैदा करने वालों से परमिट कटवा करके पैदा करते है? (हंसी)

Buses of Haryana Raodways

***936. Rao Abhai Singh:** Will the Minister for development be pleased to state—

(a) the total number of routes on which the Haryana Raodways buses are being plied in the State as on 31st March, 1974;

(b) the approximate total number of passengers travel in Haryana Roadways per day; and

(c) the approximate total number of kilometers which the buses cover per day?

शिक्षा तथा परिवहन मंत्री (श्रीमती प्रसन्नी देवी):

(क) 739।

(ख) 3.89 लाख (मार्च, 1974)।

(ग) 3.85 लाख किलो मीटरज (मार्च, 1974)।

राव बंसी सिंह: अध्यक्ष महोदय, क्या मंत्री महोदय यह बतलाने की कृपा करेगी कि हरियाणा रोड़वेज की बसों में सीट्स की रिजर्वेन्स के लिए महिलाओं के लिए कोई अलग महत्व दिया जाता है।

श्रीमती प्रसन्नी देवी: अध्यक्ष महोदय, ऐसी कोई दिक्कत महसूस नहीं होती, वैसे महिलाओं के बैठने के सिलसिले में पहले ही ध्यान रखा जाता है।

राव बसी सिंह: अध्यक्ष महोदय, क्या मंत्री महोदया यह बतायेगी कि जब से वे मंत्री बनी हैं, उसके बाद कभी इन्होंने हरियाणा ट्रांसपोर्ट की बस में सफर किया है और क्या उन्होंने यह कभी महसूस किया है कि महिलाओं के लिए अलग सीट्स की कोई आवश्यकता नहीं है?

श्रीमती प्रसन्नी देवी: अध्यक्ष महोदय, सफर तो मैंने पहले भी नहीं किया होगा, वैसे मैं आते जाते देखती रहती हूँ कि ऐसी कोई दिक्कत महसूस नहीं होती है।

मुख्य मंत्री (चौधरी बंसी लाल) अध्यक्ष महोदय, मैंने चीफ मिनिस्टर बनने के बाद बसों में सफर किया है, बाजोकात जरूरत पड़े जाती है, जैसा आप कह रहे हैं।

चौधरी दल सिंह: अध्यक्ष महोदय, क्या मिनिस्टर महोदया यह बतलाने की कृपा करेगी कि सन् 1974-75 में और कितने रूटों पर हरियाणा सरकार बसे चलाने का विचार रखती है?

श्रीमती प्रसन्नी देवी: अध्यक्ष महोदय, जैसे जैसे मांग आती जाएगी, और बसे मिलती जाएगी उनके मुताबिक जरूरत को देखते हुए बसे चलाई जाएगी।

चौधरी राम लाल वधवा: अध्यक्ष महोदय, क्या मिनिस्टर महोदय यह बतलाने की कृपा करेगी कि 31.03.70 को सरकारी और प्राइवेट कितनी कितनी बसे चलती थी और इसी तरह से 31.03.74 को कितनी कितनी?

विकास मंत्री (कर्नल महा सिंह): स्पीकर साहब, यह सप्लीमेंट्री तो इससे पैदा ही नहीं होती लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ कि जो हरियाणाप रोडवेज की बसिज चलती थी उनकी संख्या 728 थी। प्राइवेट बसों की फिगरज इस समय मेरे पास नहीं हैं।

Mr. Speaker: This Supplementary does not arise out of this Question.

चौधरी बंसी लाल: स्पीकर साहब, सब से बाद मे प्राइवेट आप्रेटर्ज मे से इसने पीछा छोड़ा थ और रिट कराके आखिरी इसकी आई थी।

Mr. Speaker: The Question of private buses does not arise out of this question.

चौधरी फूल सिंह कटारिया: अध्यक्ष महोदय, मिनिस्टर महोदया ने अभी बताया कि जैसे जैसे डिमांड होगी वैसे वैसे गाडिया चलाई जाएगी, मैं मंत्री महोदया से पूछना चाहूंगा कि जो बैकवर्ड इलाके है जहां पर बिल्कूल सड़के बनी पड़ी है और वहां पर बसें नहीं चलती। जैसे झज्जर का और साहलावास का एरिया है, वहा पर क्या उन एरियाज मे बसों को प्रेफरेन्स दी जाएगी क्योकि लोगो को वहां पपर बड़ी दिक्कत पे आ रही हैं?

श्रीमती प्रसन्नी देवी: अध्यक्ष महोदय, आनरेबल मेंम्बर अगर किसी खास जगह के बारे मे बताए तो वहाँ पर जरूरत के

मुताबिक बसें चलाने की कोशिश की जाएगी वैसे बैकवर्ड एरिया का तो पहले ही बहुत ध्यान रखा जाता है?

श्री अमर सिंह: अध्यक्ष महोदय, क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि जो गांव रोडवेज से कनैक्टिड है उन सभी गांवों में बस सेवा कब तक चालू करने का सरकार का टारगेट है।

कर्नल महा सिंह: यह तो नहीं कहा जा सकता कि बस सेवा कब तक देगे लेकिन दी जरूर जाएगी।

राव अभय सिंह: क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि आज कल जो लम्बे रूट्स की बसें चलाई जाती हैं उनमें बड़ी भीड़-भाड़ और इसके कारण क्या सरकार रिवाडी तहसील में जो लोकल रूट्स हैं उन पर कोई लोकल बसें चलाने का विचार रखती है?

कर्नल महा सिंह: अध्यक्ष महोदय, वहां पर काफी बसें चलाई गई हैं और हर महीने हम एक आध नया रूट लोकल बस का पकड़ते जा रहे हैं और जहां पर सवरियां ज्यादा होती हैं वहां पर हम नई बसें इंट्रोड्यूस कर देते हैं। खाली बस तो नहीं चलाई जा सकती है।

श्री के.एन. गुलाटी: अध्यक्ष महोदय, क्या मंत्री महोदय यह बताएंगी कि फरीदाबाद टाऊनशिप की बढ़ती हुई आबादी को देखकर, लोगों की तकलीफों का ध्यान रखते हुए कोई ऐसा प्रबन्ध

किया जा सकता है कि जिस से दिल्ली मथुरा रोडज़ से जो बसें निकल जाती है, टाउनशिप से निकलकर डी.टी.यू. बस स्टैंड को क्रॉस करें। क्या सरकार ऐसे सुझावों पर विचार करने की कृपा करेगी?

श्रीमती प्रसन्नी देवी: अध्यक्ष महोदय, वैसे तो इस प्रश्न का इस सवाल से कोई ताल्लूक नहीं है। वैसे मैं आनरेबल मैम्बर ही जानकारी के लिए बता देती हूँ कि फरीदाबाद टाउनशिप में पहले ही लोकल बस सर्विस काफी दी हुई है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि लम्बे रूट्स की बसें भाहर के अन्दर से होकर के जाएं।

जगजीत सिंह टिक्का: अध्यक्ष महोदय, जैसे मिनिस्टर साहब ने फरमाया कि रिवाड़ी में नए रूट्स जारी किए जा रहे हैं। क्या सरकार केवल रिवाड़ी में ही नए रूट्स जारी करेगी या और दूसरी जगहों पर भी नए रूट्स जारी करने का सरकार का विचार है?

कर्मल महा सिंह: अध्यक्ष महोदय, इनके अम्बाला में तो पहले ही काफी रूट्स जारी कर रखे हैं और अम्बाला डिपों में सबसे ज्यादा बसें हैं।

चौधरी पीर चन्द: अध्यक्ष महोदय, क्या मंत्री महोदय यह बताएंगे कि क्या सरकार का मिनि लोकल बसिज चलाने का कोई इरादा है?

कर्मल महा सिंह: नहीं।

चौधरी पीर चन्द: क्या मंत्री महोदय बताएंगे कि जहा लाकेल बसे चलती है वहा मिनि बसे चलाई जाएगी?

कर्नल महा सिंह: जी नहीं।

चौधरी मेहर चन्द: क्या पमंत्री जी बताएंगे कि मेरी कांसटीच्यूएँसी जो हिसार के पास है वह बहुत नैगलैक्टिड एरिया है वहां पर सड़के नहीं है और कच्चा रास्ता है तो कच्चे रास्ते पर बसे चलाई जाएगी?

कर्नल महा सिंह: कच्चे रास्ते पर बसे नहीं चलाई जा सकती। पहले आप पी.डब्ल्यू.डी. मिनिस्टर साहब से रिकवैस्ट करें कि वे वहां सड़के बनवाए।

श्री गौरी भांकर: क्या सरकार कोई ऐसा विचार कर रही है कि अगर लोकल बसे ज्यादा चला दी जाए तो जो लॉग रूटस की बसे है उन में र 1 कम हो जाए और जो भाम के वक्त जाने वाली 15-20 मील वाली सवारियां है वे उन लोकल बसों में जा सके?

श्रीमती प्रसन्नी देवी: जहां जहां लोकल बसों की जरूरत समझी जाती है वहां वहा चलाई जाती है। जहां तक मुझे ध्यान है जीन्द के बहुत सारे गावों को भाम को बसे जाती है। अगर आनरेबल मँम्बर के ध्यान में कोई ऐसा केस हो तो बताए।

चौधरी मनफूल सिंह: क्या मंत्री महोदय बताएंगी कि छूछकवास के झज्जर तक लोकल बसे चलाई जाएगी?

श्रीमती प्रसन्नी देवी: अभी नहीं।

श्री.के एन. गुलाटी: क्या मंत्री महोदया बताएंगी कि हरियाणा की बड़ी बड़ी म्यूनिसीपलिटियां या फरीदाबाद कम्पलैक्स यदि अपने बजट से मिनी लोकल बसें चलाए तो सरकार इसके लिए इजाजत देगी?

श्रीमती प्रसन्नी देवी: इस वक्त सरकार की मिनी बसिंज को चलाने की इजाजत देने की नीति नहीं है बल्कि रूटों पर हम टैम्पापे का परमिट देगे।।

मलिक सतराम दास बतरा: क्या मंत्री महोदया की कृपा करेगे कि कण्डक्टर और ड्राइवर की रोज 8 घंटे की डियूटी दी जाती है या माइलेज के हिसाब से दी जाती है?

कर्मल महा सिंह: कंडक्टर और ड्राइवर से रोज 8 घण्टे की डियूटी ली जाती है और अगर इससे ज्यादा टाईम लग जाए तो उसको ओवर टाईम दिया जाता है।

चौधरी विठ्ठल राम वर्मा: क्या मंत्री महोदया बताएंगी कि उनके हल्के इन्दरी मे भाम को कितनी बसे ठहतरती है।?

श्रीमती प्रसन्नी देवी: आनरेबल मैम्बर इन्दरी की चिन्ता न करें अपने हल्के की कोई तफलीफ हो तो बताए।

चौधरी मनफूल सिंह: मंत्री महोदया ने बताया कि झज्जर के छुछकवास के लिए बसें अभी नहीं चलाई जाएंगी। मेरा निवेदन है कि इस रूट के बीच 10-12 गांव पड़ते हैं इस लिए वहां पर बसे चला दी जाए?

श्रीमती प्रसन्नी देवी: अगर जरूरत होगी तो चला देंगे।

चौधरी फूल सिंह कटारिया: मंत्री महोदय ने बताया कि कंडक्टरों और ड्राइवरों को ओवर टाइम दिया जाता है तो क्या मंत्री महोदय बताने का कश्ट करेगे कि ज्यादा से ज्यादा कितना ओवर टाइम दिया जाता है?

कर्मल महा सिंह: अगर कोई कंडक्टर और ड्राइवर एक घंटा ओवर टाइम काम करता है तो उसको नामर्ल डियूटी के दो घंटों के बराबर का ओवर टाइम दिया जाता है। हम को ि ि कर रहे हैं कि ओवर टाइम देने की बजाए हम स्टाफ ज्यादा रखें और ड्यूटी 8 घंटे की हों।

लाला रूलिया राम: क्या मंत्री महोदया बताएगी कि कई बसें बस स्टैंडों से एक फरलांग इधर या उधर ठहरती हैं। जैसे धरोडा में हे तो क्या इस ि िकायत को दूर करने की को ि ि की जाएगी?

श्रीमती प्रसन्नी देवी: सभी जगह ऐसा नहीं होता है। कहीं कहीं ऐसी ि िकायत है लेकिन जो ड्राइवर ऐसे करते पकड़ा है उसको सजा दी जाती है।

कर्नल महा सिंह: घरोंडे की दिक्कत को दूर किया जाएगा।

राव अभय सिंह: रिवाड़ी तहसील में बहुत से गांवों में लोकल बसों की मांग है क्या इस मांग को पूरा किया जाएगा?

श्रीमती प्रसन्नी देवी: जी हां, वहां पर कई गांवों की मांग है। हमने कुछ रास्तों पर तो बसे चला दी है और कुछ रास्तों को अभी ले रहे हैं।

श्री अमर सिंह: मंत्री महोदया ने अपने जवाब में आना है कि बहुत सी जगह से ऐसी रिक्वायर्मेंट आई है कि बसे स्टैंड से एक फरलांग की दूरी पर रुकती है। तो क्या ओवर क्रॉडिंग की वजह से तो नहीं होता है? अगर ऐसा है तो इसे रोकने के क्या उपाय किए जा रहे हैं?

श्रीमती प्रसन्नी देवी: बहुत सी जगह तो मैंने नहीं कहा मैंने तो कहा था कि कहीं कहीं ऐसा हो जाता है। ऐसे केस मैंने एक दो जगह पकड़े भी हैं और हमारा स्टाफ भी इन चीजों को चेक करता है जहां ऐसा जानबूझ कर किया जाता है लेकिन मेरे ख्याल में ऐसा सवारियां ज्यादा होने की वजह से ही किया जाता है इसके लिए मैं पहले ही कह चुकी हूँ कि जैसे जैसे हमारे पास बसे आती जाएंगी हम उन्हें रूट्स पर लगाते जाएंगे।

मलिक सतराम दास बतरा: क्या मंत्री महोदय बताएंगे कि एक ड्राइवर की आठ घंटे की डियूटी खत्म होने पर उसी बस का दूसरा ड्राइवर पकड़ लेता है तो क्या यह तरीका गलत नहीं है?

कर्नल महा सिंह: हमारी कोशिश यही है कि एक बस ड्राइवर के पास ही रहे, लेकिन चूंकि ड्राइवर छुट्टी पर भी जाता है, बीमार भी हो जाता है और उसे ट्रेनिंग पर भी जाना पड़ जाता है इसलिए बदलना पड़ जाता है।

श्री बिहारी लाल बाल्मीकी: क्या मंत्री महोदय बताएंगे कि हसनपुर क्षेत्र में केवल एक एक बस चलती है और इस सम्बन्ध में कई दफा मंत्री महोदय से डेपुटी एन भी मिला है कि ज्यादा बसे चलाई जाएं। तो क्या ज्यादा बसे चलाई जाएगी।

कर्नल महा सिंह: जैसे जैसे हमारे पास बसें आती जाएंगी और जहां जहां पर मांग है हम बसें देते जाएंगे।

श्री अमर सिंह: क्या मंत्री महोदय बताएंगे कि 70 प्रतिशत बसों के कंडक्टर और ड्राइवर रोजाना बदलते हैं और तकरीबन 30 प्रतिशत परमानेंट हैं। अगर ऐसा है तो क्या इसकी वजह से बसिज में गड़गड़ नहीं होती?

कर्नल महा सिंह: एक बस के ऊपर 1.3 के हिसाब से ड्राइवर होता है इनका हम बिठा कर नहीं रख सकते, इनसे भी काम लेना पड़ता है। मैंने पहले भी बताया था कि छुट्टी और ट्रेनिंग वगैरह की वजह से ड्राइवरों पड़ता है।

Cases Pending with industrial Tribunal/Labour Court Faridabad

***925. Sh. Girish Chander Joshi:** Will the Minister for Development be pleased to state—

(a) the number of cases pending with the Tribunal/Labour Court at Faridabad as reference under Section 10 of the Industrial Disputes Act. 1947;

(b) The number of cases pending with the Tribunal/Labour Court at Faridabad under Section 32-C(2) of I.D. Act, 1947;

(c) The number of cases settled in the State; and

(d) the number of cases pending before the Government for reference?

Development Minister(Col. Maha Singh): The information as on 31-05-74 is as under:-

(a) 487

(b) 778, These cases are under Section 33-C(2) of the Industrial Disputes Act, 1947.

(c) 515, from 1.06.1973 to 31.05.1974.

(d) 71.

श्री गिरी । चन्द्र जो जी: मंत्री महोदय ने जवाब के ए और बी पार्ट में बताया कि 487 और 778 केसिज है तो क्या बताने का कष्ट करेंगे कि कितने अर्से से से पैडिंग है?

Col Maha Singh: These case are pending as on 31st May, 1974. These are the figures of the last 12 Months. Out of 487, 224 cases were pending with the Industrial Tribunal and 263 cases with the Labour Court.

चौधरी दल सिंह: क्या मंत्री महोदय बताएंगे कि ए और बी के तहत जो केस बनाए गए है उनमे से एक साल पुराने कितने है, दो साल पुराने कितने है?

Col Maha Singh: These figures are for the last 12 months. More data can be collected for which notice is required.

चौधरी राम लाल वधवा: ये जो केस बताए गए है, बहुत ज्यादा है। क्या मंत्री महोदय बतायेग कि इण्डस्ट्रीयल ट्रिब्यूनल और लेबर कोर्ट को अलग अगल बना दिया जाएगा ताकि मजदूरो का रिलीफ मिल सकें?

Col Maha Singh: There are two separate courts, But at p9resent there is only one Presiding Officer. He is presiding over two courts. Thee matter regarding appointment of a separate Presiding Officer for the Labour Court is under consideration of the Government.

श्री के.एन.गुलाटी: क्या मंत्री महोदय बताएंगे कि जो केसिज पैडिंग है। उनका फैसला जल्द करने के लिए एक-एक लेबर कोर्ट और ट्रिब्यूनल और खोलेंगे?

कर्नल महा सिंह: इस वक्त ऐसा कोई विचार नहीं है।

चौधरी मनफूल सिंह: बजीवर साहिब न फरमाया है कि 71 केसिज गवर्नमेंट के पास रैफ्रेंस के लिए है, मैं पूछना चाहता हूँ कि यह कब रैफर हुए थे?

कर्नल महा सिंह: स्पीकर साहब, यह इसी साल के है, 31 मई 1974 को गवर्नमेंट के पास 71 केसिज एग्जामिने उन के लिए थे।

चौधरी राम लाल वधवा: क्या वजीर साहिब बताएंगे कि इन केसिज मे डिसमिसल के कितने केसिज है?

कर्नल महा सिंह: डिसमिसल के केसिज थे यह तो मैं इस वक्त नहीं बता सकता लेकिन पिछले 12 महीनों मे 1870 केसिज एक साल के अन्दर आए। Of these, 515 were settled to the satisfaction of the disputant parties; 227 were withdrawn by the workers/unions; 228 were filed either because the workers did not pursue or no Industrial Dispute exist; 22 were referred for arbitrating; arbitration; 179 were rejected for reference to Court; 195 were referred to the Court; 284 were pending with the Conciliation Officers for enquiry and settlement; 89 cases are pending with the Labour Commissioner and 71 are pending with the Government.

Urban, Semi-Urban or Rural Evacuee Land

***941. Chaudhri Chand Ram:** Will the minister for Revenue be pleased to state—

(a) whether there is any Urban, Semi-Urban for Rural Evacuee Land in the Tehsil Panipat, District Karanal, Which is still to be auctioned; if so, the details thereof;

(b) the area of Agricultural Evacuee un -allotted land in villages Beholi and Goli in tehsil Panipat in the years 1964, 1965, 1966, 1967, 1968 and 1969 separately;

(c) whether there is still any Evacuee un-allotted land under the unauthorized possession of any person in Tehsil Panipat; if so, the details thereof;

(d) whether any Evacuee land has been sold/auctioned/transferred in Tehsil Panipat (Karnal District) or Tehsil Thenesal (District Kurukshetra) to non-scheduled Castes persons since 1962-63; is so, the details of such land along with reasons thereof; and

(e) the time by which all the exiting unclothed Evacuee Lands will be auctioned amongst members of Scheduled Castes in the whole of Haryana

Mr. Speaker: Next question please. The time for replaying to this question is extended. The communication received by me in this connection is as follows:

चिरंजी लाल

अर्धसरकारी पत्र, क्रमांक 9323/ज-1

राजस्व मंत्री, हरियाणा सरकार,

पुनर्वास विभाग,

चण्डीगढ दिनांक 12 जुलाई 1974

विशय: चौधरी चांद राम, सदस्य हरियाणा विधान सभा द्वारा पूछा गया तारांकित प्र न नम्बर, 941, क्या करनाल जिला की पानीपत तहसील मे भाहरी, सब- 1हरी और ग्रामीण निकासी भूमि बेचने के लिए उपलब्ध है यदि है तो उसका विवरण वर्ष 1964, 1965, 1966, 1967, 1968 तथा 1969 मे तहसील पानीपत के ग्राम बहोली तथा गोली मे कितनी कृषि योग्य बिला अलाट गुदा निकासी भूमि थी, का अलग-2 विवरण क्या अभी निकासी बिला अलाट गुदा भूमि तहसील पानीपत मे किसी व्यक्ति के नाजायज कब्जे मे है, यदि है तो उसका विवरण क्या निकासी भूमि स्थित तहसील पानीपत जिला करनाल तथा तहसील थानेसर (जिला कुरुक्षेत्र) मे वर्ष 1962-63 से किसी गैर हरिजन को बेची/नीलाम/अन्तरण की गई यदि ऐसा है तो भूमि का विवरण तथा ऐसा करने का औचित्य दिया जाए- हरियाणा राज्य मे बिला अलाट गुदा उपलब्ध निकासी भूमि जो पिछड़े वर्ग मे बेची जाती है का कितना समय लगेगा, के बारे मे सूचना-जिसका उत्तर 16.07.1974 को निश्चित है।

प्रिय श्री सरूप सिंह जी,

कृपया तारांकित विधान सभा प्र न नम्बर 941 जो 16.07.1974 की सूची मे चौधरी चांद राम, सदस्य हरियाणा विधान सभा के नाम है की ओर ध्यान देने का कष्ट करे। इस प्र न का

उत्तर अभी तक तैयार नहीं है क्योंकि जो सूचना राज्य के सभी तहसीलदार (बिक्रियों) से मांगी गई है वह अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। इस सूचना के एकत्रित करने के लिए समय चाहिए। अतः आपसे प्रार्थना है कि आप इसका उत्तर 04.08.1971 तक बढ़ाने की स्वीकृति दें। इस प्रश्न को 04.08.1974 के बाद किसी तिथि को उत्तर के लिए निश्चित कर दिया जाए।

आपका

हस्ताः

(चिरंजी लाल)

चौधरी चांद राम: स्पीकर साहब, यह तो बड़ा मामूली सा सवाल था यह इंफरमेंशन तो गवर्नमेंट के पास अवेलेबल होती है।

श्री अध्यक्ष: 31 जुलाई तक इसका टाईम एक्सटेंड कर दिया गया है।

Sugar mills

***774. Sh. Dhaja Ram:** Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state—

(a) the names of the place where sugar Mills were set up in the State during the years 1972-73 and 1973-74; and

(b) whether there is any proposal under consideration of the Government to set up any new sugar Mills in the sugar-cane areas in the State during the year 1974-75?

State Minister for Co-Operation and Local Government (Chaudhri Goverdhan Dass Chauhan):

(a) Nil

(b) yes

Revision of pay Scales

***768. Chaudhri Ram Lal Wadhwa:** Will the Minister for Finances be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to revise the pay scales of the Government employees in the State; if so, the details thereof?

Finance Minister (Sh. Ram Saran Chand Mittal):

No.

चौधरी राम लाल वधवा: क्या वजीर साहिब बतायेंगे कि प्राइस इंडेक्स जब बढ़ा है तो क्या कारण है कि उनके पे स्केलज जो है वह रिवाइज नहीं किए जाते?

श्री राम सरन चन्द मितल: स्पीकर साहब, सन् 1969 में पे स्केलज रिवाइज हुए थे उसके बाद कई तरह के अलाउंस दिए गए हैं, इसलिए अब जनरल रिविजन की आवश्यकता नहीं है।

Road from Hissar to Loharu

***784 Sh. Amar Singh:** Will the Minister for Revenue be pleased to state whether it is a fact that a portion of 3 Miles of the road leading from Hissar to Loharu via Mangali-Shirwa near harita is yet to be completed; if so, the steps taken by the Government to complete the same and the times by which it is likely to be completed?

Revenue Minister (Pardit Chiranji Lal Sharma):

(1) Yes, the road is incomplete and a length of 6.20 K.M. has not so far been constructed. The correct name of the scheme is the construction of road from Hissar Saharwa-Iwsharwal road-section-Hissar Miran upto Tosham Siwni Raod.

(2) In view of the small outlay for roads in the 5th Five Years plan recommended by the Planning Commission, no target date can be fixed for completing the incomplete portion of this road.

श्री अमर सिंह: क्या आनरेबल मिनिस्टर साहिब के नोटिस मे है कि इस 44 मील लम्बी रोड मे सिर्फ 2.6 किलोमीटर का टोटा जिस पर मिट्टी भी पड़ी हुई है न बनने की वजह से सारा रास्ता रुका हुआ है? अगर है, तो वह कब तक बना दिया जाएगा?

Pandit Chiranji Lal Sharma: Sir, I Just submitted that the road is incomplete. As for plying of buses on this road, I have no know ledge.

Plans of the Factories

***761. Chaudhri Shiv Ram Verma:** Will the Minister for Social Welfare and Taxation be pleased to state—

(a) the district-wise total number of plans of factories which are proposed to be installed in the State and are lying pending with the Town and Country planning Department for approval; and

(b) the district wise number of such plans which are lying pending for the last six months, one year and two years, separately?

Social welfare and taxation Minister (Shri Shyam Chand):

(a) The district wise break up to building plans of factories which were pending as on 1-06-1974 with the Town and Country Planning Department is as under:-

(i)	District Gurgaon	51
(ii)	District Kurukshetra	1
(iii)	District Hissar	4
(iv)	District Bhiwani	1

(b) No plans have been pending for more than three months.

Mr. Speaker: Question hour is over please.

चौधरी दल सिंह: स्पीकर साहब, मेरा क्वे चन 789 रह गया था, अभी पांच मिनट का समय रहाता है, इस लिए उस का

जवबा अगर आ जए तो मेहरबानी होगी। मै सप्लीमेंटरी नही पूछूंगा।

Mr. Speaker: No please, The hon. Member was not present in the House at that time.

Chaudhri Chand Ram: Sir, there are still five minutes to three.

Mr. Speaker: The hon. Member did not authorize anybody else to put the question on his behalf.

ध्यानपकर्षण प्रस्ताव

Mr. Speaker: There is call attention Motion of Sh. Ram Lal Wadhwa and Chaudhri Shiv Ram Verma regarding a matter of urgent public importance pertaining to an alleged incident of Barwala District Hissar of July 10, 1974. The notice is admitted. The Hon. Member may read his Call attention Motion.

Chaudhri Ram Lal Wadhwa (Karnal): Sir, we beg to draw the attention of the House to a matter of urgent public importance that a sensational news had appeared in the Times of India dated 15th July, 1974, that 15 tranders of Barwala in Hissar District tied with ropes were made to run like cattle's through the bazaars and streets of the is of urgent public importance. It relates to the Law and Order of the Home Minister Haryana to make a statement on the incitement. There is great resentment and terror in the public on account of this incident.

We beg to give notice for Call Attention to a matter of urgent Public importance under rule 73 of Rules of Procedure and Conduct of Business in Haryana Legislative Assembly and request the Government to make a statement on the incident.

It papered in the Newspapers that a minor altercation between Mr. Prem Lal young Shop-keeper and a Police Constable over a trifle issue led to a scuffle between them. It is reported that a Police Constable in plain clothes was standing in front of shop of Mr. Prem Lal. Mr. Prem Lal asked him if he wanted some thing from his shop. The Constable retorted angrily by saying what was there with the Shop-Keeper? Hot words exchanged and scuffle followed.

The Policeman bought five other Constables in uniforms and thrashed the boy in the main street after taking him from the local bus Stand. This enraged the traders and they pulled down the shutters and collected in front of the police Station. They raised slogans and threw the stones when the main gate of the Police Station was closed. On seeing the crowd disappeared. Drama ended at 10.30 P.M.

Next morning Police has taken into custody about 15 traders. They were allegedly subjected to third degree methods in the Police station. In the evening, they were paraded in the Town With only under wars on. Many shops were closed in panic against the police atrocities. This is the worst type of incident of police atrocities in Haryana.

This news has spread great panic and terror in the State. The situation arise from the news is most serious and

requires immediate attention of the Haryana Government as will as the House of Haryana Assembly.

Chief Minister (Chaudhri Bansi Lal): 26th.

Mr. Speaker: The statement will be made on the 26th July, 1974.

चौधरी चांद राम: स्पीकर साहब, दो काल अटै ांन मो ान मैने भी दिए थें ।

Mr. Speaker: There are two Call Attention Motions by Chaudhri Chand Ram and another on the same subject. They are pending because Only one matter can be raised at one sitting.

चौधरी चांद राम: स्पीकर साहब, एक तो पहले आई थी और एक बाद मे आई थी ।

Mr. Speaker: This is under examination
(Interruption) This is not signed by anybody.

श्री अमर सिंह: स्पीकर साहब, मैने तो साईन करके भेजी थी ।

Mr. Speaker: Those two motions are pending.

Sh. Amar Singh: My Call Attention Motion is also pending?

Mr. Speaker: Yes.

चौधरी चांद राम: स्पीकर साहिबा, वह कौन सी थी जो साईन्ड नहीं है।

श्री अध्यक्ष: जो आज आई थी।

कार्य मंत्रणा समिति का तृतीय प्रतिवेदन

Mr. Speaker: I present the Third Report of the Business Advisory Committee.

The Committee, after some discussion, Recommended that the Business on 16th July, 1974, be transacted as follows—

16 July, 1974

I. Questions Hour.

II. Third report of the Business Advisory Committee.

III. Presentation of second Preliminary Report of the Committee of Privileges and asking for extension of time for the presentation of the final Report.

IV. The Haryana Canal and Drainage Bill, 1973, as reported by the Select Committee.

The Committee further recommended that Sabha might also meet on the 17th July, 1974, to resume the consideration of the Haryana Canal and Drainage Bill, 1973, as reported by the Select Committee, if it was not passed on the 16th July, 1974. The House will meet again on 26th July, 1974, at 2.00 P.M. to consider the remaining Business.

Chief Minister (Chaudhri Bansi Lal): Sir, I beg to move

That this House agrees with the recommendations contained in the Third Report of the Business Advisory Committee.

Mr. Speaker: Motion Moved—

That this House agrees with the recommendations contained in the Third Report of the Business Advisory Committee.

Mr. Speaker: Question is—

That this House agrees with the recommendations contained in the Third Report of the Business Advisory Committee.

The motion was carried.

वि शेशाधिकार समिति का द्वितीय प्रारम्भिक प्रतिवेदन तथा समय
बढाना

15.00 बजे

Shri Gulab Singh Jain (Chairman of the Committee of privileges): Sir, I beg to present the Second Preliminary Report of the Committee of Privileges of the Haryana Vidhan Sabha on the matter in regard to the Question of alleged breach of privileges against Chaudhri Hardwari Lal M.L.A., for writing derogatory remarks against the Speaker and the House in the booklets entitled. "A Chief

Minister Runs Amuck” and “Emergence of Rough and Corrupt Politics in India”

Sir, I also beg to move—

That the time for the presentation of the Final Report be extended upto the 28th February, 1975.

Mr. Speaker: Motion Moved—

That the time for the presentation of the Final Report be extended upto the 28th February, 1975.

चौधरी चांद राम : स्पीकर साहब, इस पर थोड़ी सी आव्जर्वे ान करनी है.

श्री अध्यक्ष: यह तो टाईम ऐक्सटेंड कर रहे है, इस पर क्या कहना है?

चौधरी राम लाल वधवा: इस पर कहना यह है और पूछना यह है कि टाईम की ऐक्टें ान मांगते वक्त सैंकिंड प्रिलिमिनरी रिपोर्ट पे ा रक रहे है लेकिन यह सैंकिंड प्रिलिमिनरी रिपोर्ट क्या है उसका हमें पता नही लगा कि क्या है क्योकि हमे वह दी नही गई हे। हम यह जानना चाहते है कि इतना अर्सा इस मामला को चले हो गया और काफी देर से यह पिविलेज इ ू चल रहा है और अभी तक फाईलन रिपोर्ट क्यो नही आई है?

श्री अध्यक्ष: इसमें यह है कि बीच में प्रिविलेज कमेटी की टर्म खत्म हो कर नई कमेटी बन गई और अब वह इसे ऐग्जामिन कर रही है।

Mr. Speaker: Question is—

That the time for the presentation of the Final Report be extended upto the 28th February, 1975.

The motion was carried.

औचित्य प्र न—दी हरियाणा कैनल एण्ड ड्रेनेज बिल 1973 के सम्बन्ध में

Chaudhri Ram Lal Wadhwa: On a point of order, Sir. Mr. Speaker the same things has been repeated today. This Haryana Canal and Drainage Bill has been presented to the house, but without any statement of objects and reasons.

Mr. Speaker: This bill has already been introduced. it has gone to the Select Committee. Today you will consider the bill as reported by the Select committee

Chaudhri Ram Lal Wadhwa: What is the motion? The Motion on the agenda is—

“ **A Minister:** to move that the Haryana Canal and Drainages Bill, 1973, as reported by the Select committee be taken into consideration.

ALSO to move that the Haryana Canal and Drainage Bill, 1973 as reported by the select Committee be passed.”

Mr. Speaker: Order please.

Chaudhri Ram Lal Wadhwa: The Question is that the Bill, as reported by the Select Committee, is to be passed and not the Bill which was previously introduced to presented to the house. Now this Bill, is without the statement of objects and reasons, without the financial memorandum and without the memorandum regarding delegated legislation. Rule 128 says-

“As soon as may be, after a bill has been introduced, the bill, unless it has already been published, shall be published in the Gazette:

Provided that the Speaker, on request being made to him, may order the publication of any bill (together with the Statement of Objects and Reason, the memorandum regarding delegation of legislative power and the financial memorandum accompanying it) in the Gazette.....

and Rule 126 reads—

“A bill involving proposals fro the delegation of legislative power shall further be accompanied by a memorandum explaining such proposals and drawing attention to their scope and stating also whether they are of normal or exceptional character.”

Then Rules 125 says—

“(1) A bill involving expenditure shall be accompanied by a financial memorandum which shall invite particular attention to the causes involving expenditure and

shall also give an estimate of the recurring and Non-recurring expenditure involved in case the Bill is passed into laws.

And this bill does not fulfill these requirements of the Rules.

Mr. Speaker: Which rule are you citing?

Chaudhri Ram Lal Wadhwa: Rules 125, 126 and 128.

Mr. Speaker: These rules are not relevant to this Bill. You please read rule 149 regarding procedure after presentation of report.

Chaudhri Ram Lal Wadhwa: This Rule reads—

“(1) After the presentation of the final report of a Select Committee on a bill, the member-in-charge may move—

(a) that the Bill as reported by the Select committee be taken into consideration: Provided that any member of the Assembly may object to its being so taken into consideration if a copy of the report has not been made available for the use of members for seven days and such objection shall prevail unless the Speaker allows the reports to be taken to consideration.”

लेकिन मेरी सबमिशन यह है कि यह जो बिल एज रिपोर्टिड बाई दि सिलैक्ट कमेटी सदन में पेश किया गया है यह रूलज 125, 126 और 128 के अगैस्ट है क्योंकि यह इन रूलज के प्रोविजनज को पूरा नहीं करता। जो आरिजनल बिल था और जो

सदन मे पहले इन्ट्रोडयूस किया गया था उसमे स्टेटमेंट आफ आब्जेक्ट्स एंड रीजंज, फाईनै ल मैमोरैंडम और मैमोरैंडम रिगार्डिंग डेलिगेटिड लैजिस्ले इन दिया हुआ था लेकिन अब जो यह बिल एज रिपोर्टिड बाई किद सिलैक्ट कमेटी आया है इसमे यह सब कु छ नही है। हसमे ऐसा है कि सिलैक्ट कमेटी भी रिपोर्ट के आधे पेज पर बिल एज रिपोर्टिड बाई दि सिलैक्ट कमेटी दिया हुआ है लेकिन औरिजनल बिल मे जो पहले फयनै ांल मैमोरैंडम स्टेटमेंट आफ आब्जेक्ट्स एक रिजंज मैमोरैंडम रिगार्डिंग डेलिगेटिड लैजिस्ले इन दिये हुए थे वह अब इसमे नही दिये गये और वह दिये जाने चणिये थे क्योकि उनके बगैर बिल इनकम्प्लीट है और रूल्ज के अनुसार यह नही पे ा किया गया हैं। मिनिस्टर साहब जो अब बिल पास करवाने के लिए सदन मे पे ा कर रहे है वह बिल एज रिपोर्टिड बाई दि सिलैक्ट कमेटी कर रहे है लेकिन इसमे रूल्ज के अनुसार वे चीजे नही है। अब सवाल यह है कि क्या विदआउट दीज थिंगज यह बिल सदन मे पे ा किया जा सकता है? With this Bill, there will be no financial memorandum. Also, there will be no memorandum regarding delegated legislation and no statement of objects and reasons.

Mr. Speaker: We are considering the same Bill, but as reported by the Select committee.

Chaudhri Ram Lal Wadhwa: Now the Bill will be passed as reported by the Select Committee and not the original Bill. The hon. Minister is going to move that the Bill, as reported by the Select Committee, Should be passed and

not the original Bill. It means that this bill will be without these three requirements of the provisions of the Rules.

Mr. Speaker: These requirements have been complied with by the original Bill.

Chaudhri Ram Lal Wadhwa: The original bill is not going to be passed.

Mr. Speaker: If they are there with the original Bill, they will be with this bill as reported by the Select Committee.

Chaudhri Ram Lal Wadhwa: How will the be passed? The Hon. Minister will be moving that this bill be passed, as reported by the Select Committee, and not the original Bill.

Mr. Speaker: The Select Committee has recommended amendments or changes in the clauses of the Bill.

Chaudhri Ram Lal Wadhwa: This is not sufficient.

Mr. Speaker: It has not recommended any changes in the Statement of objects and reasons etc. I over rule your objection. It is not valid.

दी हरियाणा कैनल एण्ड ड्रैनेज बिलए 1973

सिंचाई तथा बिजली मंत्री (श्री बनारसी दास गुप्त):
श्रीमान् मै प्रसताव करता हूं।

कि प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदन रूप में हरियाणा नहर तथा जल निकास विधेयक, 1973 पर विचार किया जाये।

Mr. Speaker: Motion moved—

That the Haryana Canal and Drainage Bill, 1973, as reported by the Select Committee, be taken into consideration.

चौधरी दल सिंह (जीन्द): स्पीकर साहब, हरियाणा नहर तथा जल निकास विधेयक, 1973 सदन के सामने पे 1 है और मैं
.....

श्री बनारसी दास गुप्त: दल सिंह जी आप तो मेंटर थे कमेटी के।

चौधरी दल सिंह (जीन्द): मैं तो आप की तारीफ ही कर रहा हूँ और

Mr. Speaker: A member, who was a member of the Select Committee, cannot oppose the Bill, if he has not given a note of dissent.

चौधरी दल सिंह: मैं इसे अपोज नहीं कर रहा हूँ। मैं यह अर्ज कर रहा था कि इस बिल की तार्ड करता हूँ और मैं यह बात साफ तौर पर कह देना चाहता हूँ कि यह बिल हरियाणा के किसानों के लिये और हरियाणा की 95 फीसदी पापूले इन के लिये बहुत ही अमह बिल है। मैं यह भी अज्र करता चाहता हूँ कि सिलैक्ट कमेटी ने अपनी 10 मीटिंग में इसे थारोली एग्जामिन

किया है और बहुत मेहनत के साथ जाच पड़ताल करके अमेंडमेंट्स इस में सजैस्ट की है। जहां मैं इसे स्पॉर्ट करता हूँ वहां यह कहे बगैर भी नहीं रहा सकता कि इसे अमेंड करने में हमारे हाउस के मेंबर चौधरी मेयर चन्द जी का बहुत हाथ है और इसी प्रकार सरकारी कर्मचारियों को भी बहुत हाथ है खास तौर पर कमि नर फार इरीगे ान एंड पावर श्री केप्रिहन साहब, ने बहुत मेहनत की है। मैं इस बिल की ताईउ करते वक्त इन सक साहिबान को अपनी तरफ से मुबारिकबाद पे ा करता हूँ। इसके साथ साथ गवर्नमेंट ने यह भी कहना चाहता हूँ कि चौधरी मेहर चन्द जी ने इसके बनाने में बहुत मेहनत की है इसलिए आगे लिए भी जब कोई जरूरी बिल सिलैक्ट कमेटी को भेजा जाये तो उसमें चौधरी मेहर चन्द जी को जरूर मेंबर लिया जायें।

Shri Amar Singh (Bawani Khera-S.C): Mr. Speaker, Sir, the Haryana Canla and Drainage Bill, Which is before the House, was originally introduced in November, 1973. उसके बाद 16 नवम्बर को जब हाउस में इन्ट्रोड्यूस हुआ तो उस पर विचार करने के लिए एक सिलैक्ट कमेटी मुकररर हुई जिस ने 31 मार्च 1974 तक छान बीन करके रिपोर्ट पे ा करनी थी। वह बिल सिलैक्ट कमेटी की रिपोर्ट पे ा करने के बाद आज हाउस में जेरेगार है। स्पीकर साहब, इसमें कोई दो राय नहीं कि नौरदन इंडिया कैनाल ड्रेनेज एक्ट 1973 तकरीबर 100 साल के बाद के बाद अमेंउ हो रहा है और इस दौरान यह एक्ट किसानों को डैमेज करता रहा। कर्मचारी नहर में खुद गड़बड़ करके डैमेज

किसान के कंधे पर डाल देते थे। पिछले दिनों इस एक्ट के तहत यह ज्यादाती होती रही लेकिन आज जो बिल हमारे सामने आया है, इसकी छानबीन करके जो कमियां सामने आई थी उन को दूर करने के लिए बहुत कोशिशें की गईं और छानबीन की गई लेकिन फिर भी स्पीकर साहब, क्लोज 28, 29 और 31 इन तीनों क्लोजिज के बारे में थोड़ा सा अर्ज करना चाहता हूँ। इनमें अब भी थोड़ी सी एम्बिग्विटी है जो किसान के लिए घातक साबित हो सकती है। क्लोज 28 में लिखा है—

“If water supplied through a canal is used in an unauthorised manner, and if the person by whose act or neglect such use has occurred cannot be identified, the person who has derived or may derive or may derive benefit therefrom shall be liable to the charges prescribed for such use.”

स्पीकर साहब, प्रायः यह देखने में आया है कि 10-20 भोयर होल्डर्स के आउट-लैट को, एक आदमी डैमेज कर जाता है तो उससे खड़ी फसल को नुकसान हो जाता है और दूसरी तरफ कईयों को इससे फायदा हो जाता है क्योंकि जिस आदमी ने आउटलैट डैमेज किया है वह आईडेंटिफाई नहीं होता। यहां आईडेंटिफाई वाली बात ठीक नहीं है क्योंकि तवान के कैसिज कोर्ट ने करने होते हैं। जब पुलिस रिपोर्ट करके भेजती है तो किसी भी केस में पुलिस की यह रिपोर्ट नहीं होती कि पुलिस ने आईडेंटिफाई मुलजिम कर लिया है? अगर एक आदमी इन्टैग्रेली भारत करके आउटलैट को डैमेज कर जाता है तो उसकी

रोकथाम के लिए हमारे पास कोई चारा नहीं है जिसकी बिना पर हम उसको आईडेंटिफाई करके पकड़ सके। अगर 50 भोयर होल्डर्ज का आउट लैट हो तो आउटलैट डैमेज होने से इन में से 20 को तो बैनिफिट हो गया और जिसका खेत बिल्कुल आउट लैट के साथ लगता है उसको अधिक नुकसान हो गया, उसकी फसल तबाह हो गई और इतना होने पर भी उस पर तवान लग जाता लग जाता है। इस तरह से उसको बहुत नुकसान होता है। मैं मंत्री महोदय से निवदेन करना चाहता हूँ और उन के नोटिस में लाना चाहता हूँ कि अगर इसके दो पार्ट कर देते तो अच्छा था जैसा कि 50 भोयर होल्डर्ज का आउट लैट है और आउट लैट डैमेज होने से 25 को फायदा और 25 को नुकसान हो गया तो इस सुरत में अगर इसमें एक सब-कलाज जोड़ दी जाए कि जिन को डैमेज हुआ है उनको कम्पेंसैट कर किया जाए और जिन को फायदा हुआ है उन पर तवान लगा दिया जाए तो ठीक रह क्योंकि मौगा तोड़ने वाला आईडेंटिफाई तो होता ही नहीं कुछ कैसेज आईडेंटिफाई हो जाते हैं कुछ नहीं होते। गांव का कोई आदमी बताता नहीं और न कोई विशेष छानबीन करता है। इस लिए मेरी अर्ज यह है कि मिनिस्टर साहब इस बात पर गौर करें कि एक सब-कलाज और जोड़ दी जाए जिस से किसी को नाजायज नुकसान न हों। मिनिस्टर साहब गौर करें कि तवानके कैसेज बहुत पुराने होने के बाद अदालत के आते हैं, इस प्रोसेस को ठीक करना जरूरी है। जब आफिशियल कंसन्ड ओवर सियर एस.डी. ओ. वहां से बदल जाते हैं उस के बाद ये कैसेज अदालत में आते

हैं। कई कई तो चार चार, पांच-2, छः- छः साल के बाद टाईम लिमिट कु करर कर दी जाए कि तीन महीने के बाद या छः महीने के बाद कोर्ट में तवान केसिज आ जाने चाहिए। स्पीकर साहब, मैंने देखा है, बहुत सारे केसिज आठ-आठ साल पुराने हैं जिन का न कोई सिंर है, न पैर है, किसान के ऊपर तवान तजबीज करके अदालत में भेज देते हैं। कई-कई तारीखें पड़ती रहती हैं कई केसिज ऐसे होते हैं जो मेन्टेनेबल नहीं होते, कई केसिज की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती और फिर ऊपर से कई गुणा तवान लग जाता है। तो स्पीकर साहब, नइ पर टाईम लिमिट होनी चाहिए कि तवान के केसिज बनें उन को 24 घन्टे के अन्दर-अन्दर एस.डी.ओ. (सिविल) साहब द्वारा एग्जामिन किया जाना चाहिए, इन्सपैक्शन करना चाहिए और देखना चाहिए कि यह कट है या ब्रीच। अगर गजेटिड अफसर द्वारा टुवेंटी-फोर आवर के अन्दर-अन्दर इन्सपैक्शन हो जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा, एक तो छानबीन हो जाती है और दूसरे असली बात का पता लग जाता है।

इसके अलावा मैं अर्ज करना चाहता हू कि आवर सीयर, लास्ट डेट आफ इन्सपेक्शन रिपोर्ट टेलीग्राम की कापी, एस.डी.ओ. और डिविजनल कैनल अफसर को भेजता है। उस की एक कापी एस.डी.ओ. सिविल के पास भी जानी चाहिए और सीयर लास्ट डेट आफ इन्सपेक्शन से डेट आफ डिटैक्शन तक जो डेट उस को सूट बैठती है वही लास्ट डेट आफ इन्सपैक्शन रख

लेता है और टेलीग्राम भेज देता है। तवान जो लगता है वह लास्ट डेट आफ इंस्पैक्ट इन से लास्ट डेट आफ डिटैक्ट इन तक लगता है। इस तरह ओवर सीयर लास्ट डेट आफ इंस्पैक्ट इन अपने हिसाब से भरता है। एक आदमी जिसको बचाना चाहे बचा देता है, जिसको दबाना चाहे दबा देता है। इस लिए जो ओवरसीयर कंसन्ड हो उसकी इंस्पैक्ट इन रिपोर्ट एस.डी.ओ. डिविजनल कौनाल अफसर और एस.डी.ओ. सिविल के पास मन्थली जानी चाहिए ताकि यह पता लग सके कि क्या पिछले हफ्ते में आवरसीयर ने इंस्पैक्ट इन किया है, यहा उसने पिछले हफ्ते में किया है? वह इसको चैक करे आवरसीयर दो तीन दिन पीछे की डेट भजे देता है क्योकि उसका किसी के पास कोई रिकार्ड नहीं होता। इससे किसान को नुकसान होता है क्योकि आवरसीयर लास्ट डेट आफर इंस्पैक्ट इन से डेट आफ डिटैक्ट इन तक तवान लगाते है अगर वह एक हफ्ते का फर्क डाल दे तो किसान को एक हफ्ता पीछे तक का तवान देना पड़ता है। पिछले हफ्ते जब वह इंस्पैक्ट इन करने गया था, उस दिन करने गया था, उस दिन से उस दिन (आज तक) तवान देना पड़ता है, इसके बारे में सरकार ध्यान दे और तजवीज पर अमल किया जावें।

अब मैं कट की बाबत अर्ज करना चाहता हूं यहा पर जिक्र आया है कि कट को कैसे रोका जाए। कई जगहों पर कट होते है और कई जगहों पर इन्टैन इनली ब्रीच का कट बना देते है, कर्मचारी आपस में मिल कर यह काम करते है। जैसा कि

प्रौसीडिंग से जाहिर होता है सिलैक्ट कमेटी को कमि नर तथा सैक्रेटरी ने चीफ इंजीनियरों वगैरा ने इसकी रोकथाम के लिए बताया है लेकिन फिर भी मैं एक बात अर्ज करना चाहता हूँ कि विकली फोर्टनाईटली या मन्थली, डिविजनल कैनाल आफिसर का इंसपैक्टिव इन होना चाहिए जिससे चैक रहे और कर्मचारी को डर रहे। यह नहीं होना चाहिए कि ब्रीच का कट बना दिया जाए। स्पीकर साहब, आपकी कांस्टीचुएँसी का एक बास गांव है, वहां सुन्दर ब्रांच मे ब्रीच हो गया और तकरीबन तीन-चार फुट लम्बा हो गया। एस.डी.एम. और डिप्टी कमी नर साहब मौके पर चले गए। ऐग्जैक्टिव इंजीनीयर इरीगे इन उन के साथ थे। उस गांव मे गेंहू के भरोटे कटे हुए थे वे 10-12 किल्ले मे 2-3 फुट पानी मे पड़े रहे, सारी फसल बरबाद हो गई। तीन अफसरान की रिपोर्ट यह थी कि ब्रीच है लेकिन फिर भी वह ब्रीच कट मे बदल गया। वह कट का केस कोर्ट मे आया और कोर्ट से उन किसानों की रिहाई हुई। इस तरह की स्थिती आम तौर पर हो जाती है।

पहले जो सन् 1873 का नार्दर्न कैनाल एण्ड ड्रेनेज एक्ट था जो कि सैनट्रल गवर्नमेंट के तहत होता था अब हमारी हरियाणा सरकार के तहत हरियाणा कैनाल एण्ड ड्रेनेज बिल 1973 आया है। इसमे बहुत सारी बातों की रोक-थाम की गई है। मेझे पूर्ण वि वास है कि अब आइन्दा किसी के साथ ज्यादती नहीं होगी। जो पिछले दिनों होती रही हैं। जिन चीजों पर मैंने स्पीकर साहब, आपके द्वारा सरकार का ध्यान दिलाया है मैं समझता हूँ कि

सरकार इनकी और ध्यान देगी। स्पीकर साहब, यह बेहतरीन बिल है। यह 88 परसैन्ट लोगो का कवर करता है जो खेती बाड़ी का काम करते है। यह आपके देखने मे भी आया होगा कि बहुत सारी जगह आवरसीयर भारारत करके किसानों को तंग करते है।

स्पीकर साहब, एक चीज की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि मैयरमेंट करने के लिए इरीगे ान जाता है। वह चार चार हफ्ते बाद जाता है। जब उसको यह पता ही नहीं लगता है कि किसान ने दो बार पानी दिया या तीन बार पानी दिया है। जब वह मैयरमेंट करने के लिए जाता है उसके पास कोई पैमाना नहीं होता है कि कितना पानी इस बार मे लगा है। उसका यों ही अन्दाजा लगा कर लिख दिया जाता है। बहुत सारी जगह यह सवाल पैदा होता था कि बारी से 24 घण्टे मे किन किन लोगों को कितने कितने घन्टे पानी दिया गया और अन-अथोराइजड तरीके से कितने लोगों को पानी दिया है अब इसमे सारी बातें आयी हे। इस तरह की ज्यादातियां होती थी। यह जो बिल जैरे बहस है इसके पास करने के बाद यह ज्यादातियां किसानो के साथ नहीं होगी इसके साथ-साथ मै यह भी निवेदन करुंगा कि यह इतना अहम बिल है इसकी इम्पलीमेंट ान के लिए जहां पैट्रोलिंग सैल बन रहा है वहां नहर के कटों की देखभाल और तावान की मदद को खासतौर पर उसके अन्दर डाल दिया जाए ताकि आइनदा किसी किस्म की ि ाकायत न हो सके। मै स्पीकर साहब, गवर्नमेंट जो यह बिल लायी है इसकी पुरजोर हिमायत करता हूं और जो

पिछले दिनों हमारे नोटिस में विचारित आती रही है वे इस बिल के पास होने के बाद दूर हो जाएंगी।

श्री गौरी भांकर (नरवाना): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल का स्वागत करता हूँ। यह बिल बहुत सोच समझ के बनाया गया है दो तीन बातों के बारे में आपके द्वारा सरकार से प्रार्थना करना चाहता हूँ और आशा है कि सरकार उन पर विचार करेगी। क्लोज 15 में महज लफ्ज कैनल है लेकिन जो पानी दिया जाता है वह कैनल माइनर से दिया जाता है। इस पर कोई व्यक्ति कोर्ट में इस लफ्ज के खिलाफ आवाज उठा सकता है। हम कैनसल से पानी नहीं लेते हैं। अगर इसकी जगह कैनल माइनर कर दिया जाए तो ठीक रहेगा, क्योंकि हमें कैनल माइनर से पानी मिलता है। दूसरे क्लोज 55 के अन्दर डिप्टी कुलैक्टर को बारबन्दी की पावर है। बारबन्दी तो डिप्टी कुलैक्टर करता है। बहुत दफा ऐसा भी होता है कि कुद आदमी उसकी चलने नहीं देते इस लिए मैं आपके द्वारा सरकार से प्रार्थना करूंगा कि डिप्टी कुलैक्टर को तवान लगाने की पावर भी दी जानी चाहिए। जो बारबन्दी नहीं चलने दे उस पर तवान लगाने की डिप्टी कुलैक्टर को पावर होनी चाहिए।

तीसरी चीज जो आजकल झालर लगा लेते हैं, बगैर किसी की अप्रुवल के उससे क्या होता है कि झालर लगाने के बाद, उसके आगे जिस आदमी का अगला नाका होता है उसके पास पानी नहीं पहुंचता। वह अगला आदमी मारा जाता है क्योंकि

वह झालर सारी नहर तक का और माइनर तक का पानी खींच लेता है। अगले आदमी को पानी लगाने के लिए कम से कम खाल भरने के लिए घन्टा डेढ घन्टा लगता है इसलिए उस आदमी का तो सारा वार ही खत्म हो जाता है। गवर्नमेंट की अप्रूवल के बगैर झालर नहीं लगाने की इजाजत मिलनी चाहिए। अगर अप्रूवल से झालर लगे तो अगले आदमी को उस पानी को कम्पनसै इन दिया जाना चाहिए।

चौथी बात यह है कि हमारे जो नहरो मे ब्रीच और कट होता है, जो हमारे नहर के अफसर होते है उनकी गलती की वजह से , उनकी लापरवाही की वजह से जो ब्रीच हो जाते है उनको कट बना दिया जाता है। इसके लिए मै आपके द्वारा सराकार से प्रार्थना करुंगा कि नहर का कोई अफसर कट या ब्रीच की इन्कवायरी न करें। उनकी इन्कवायरी किसी डी.सी. या एस.डी.एम. के थ्रु करायी जाए ताकि इम्पार्ल इन्कवायरी हो सके। नहर के अफसर जो कट न हो तो भी उसका कट बना देते हैं। जिस आदमी की गलती हो उसी को सजा मिलनी चाहिए क्योकि महकमे के अफसर अपने आप को बचाने के लिए जो ब्रीच होता है उसको कट बना देते है। इस एक्ट के अन्दर यह दिया हुआ है कि जिस डिपार्टमेंट की बात है उसी ने इन्कवायरी करनी है तो लोगों पर यानी जमींदारो पर इसकी जिम्मेवारी डालेंगे। इस लिए मेरा निवेदन है कि इन्कवायरी एस.डी.एम. यह डी.सी. के जरिए कराई जानी चाहिए और जो कट का तावान लगना हो वह भी उनकी

मन्जूरी से लगना चाहिए। दूसरे जो कट का तावान डाला जाता है वह उस आस पास की सारी जमीन पर डाला जाता है तो सरकार को फसल का मुआवजा देना चाहिए। अगर एक आदमी कट करता है उसका सारा तावान उस आदमी पर लगना चाहिए जिसने कट किया है सारे जमींदारों पर नहीं लगना चाहिए। इसमें एक चीज और भी है जो हमारे मोघों है जो जमींदार बाबू को पैसे दे देते है उसका मोघा तो खुला चलता है, उसको नीचे लगा देत है और जो जमींदार पैसे नहीं देते है उसका साइज कम कर देते है। उसके मापने के लिए, देखने के लिए कोई तरीका नहीं है। इसलिए मैंने यह पहले भी कहा था और आज भी आपके द्वारा सरकार से कहता हूं कि हर मोघे पर मीटरगेज लगना चाहिए ताकि हर अनपढ़ जमींदार को भी यह पता लग सके कि मोघे में पानी कम जा रहा है या ज्यादा आ रहा है यह सरकार को जरूर करना चाहिए क्योंकि आवरसीयर लोगो को परे गान करते है, जमींदारो को लूटते है। इसलिये मैंने बहुत जरूरी बाते आपके सातने रखी है आ ग है सरकार इन पर ध्यान देगी। आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया मैं आपका धन्यावाद करता हूं।

चौधरी विठ्ठल राम वर्मा(नीलोखेड़ी): आदरणीय अध्यक्ष महोदय, यह हरियाणा कैनाल एन्ड ड्रैन्ज बिल 1973 अभी सिलैक्ट कमेटी से होकर उसकी रिपोर्ट के साथ यहा सदन में विचार के लिए आया है। मैं भी सिलैक्ट कमेटी का मँम्बर था। तो इसमें मैं सारी कमेटी के बारे में कुद कहूँ कि किसने कितना काम किया है,

कितना नहीं किया वह अच्छा नहीं लगता। मैं एक माननीय सदस्य जो इस कमेटी के मैम्बर थे चौधरी मेहर चन्द, उन्होंने इस बिल पर सभी मैम्बरों से ज्यादा मेहनत की है, इसलिए मैं उनकी प्रशंसा किए बिना नहीं रह सकता। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा सदन को जानकारी देना चाहता हूँ कि उन्होंने इसके लिए बहुत मेहनत की। उसके साथ ही साथ जहाँ महकमे के इंजीनीयर और अफसरान ने मेहनत ही वहाँ हमारे सचिव सिंचाई विभाग ने भी कमेटी को बहुत अच्छा सहयोग दिया जिसके फलस्वरूप बहुत ही विघ्नता से यह बिल सिलेक्ट कमेटी से विचार होकर तीन-चार महीने में ही फाईनल कर दिया गया है। इसके अलावा अध्यक्ष महोदय, जो इस बिल की क्लोज पांच है उस पर आपके द्वारा सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूँ।

Mr. Speaker: The hon. Member cannot oppose the clause.

चौधरी शिव राम वर्मा: मैं विरोध नहीं कर रहा हूँ और विरोध करूंगा भी नहीं। विरोध करने का मेरा अधिकार भी नहीं बनता है। मैं तो उस पर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ सिर्फ एक आवासन के लिए जो क्लोज पांच के अन्दर जो सरकारी ट्यूबवैल है उनसे 150 मीटर तक किसानों को ट्यूबवैल लगाने पर पाबन्दी लगाई है उसमें जो पाबन्दी लगी है उस पर कमेटी कैसे सहमत हुई, वह मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ:—

“On reconsideration it was decided that clause 5 will be redrafted in the meeting of the Committee to be held on the 28th March, 1974”

उस 28 मार्च की मीटिंग में विचार विमर्श होकर फिर जो बात आयी, उसके आधार पर यह लिखा गया।

“Clause 5

While considering clause 5 of the Bill, Members of the Committee were of the view that this limit of 150 meters from the augmentation tubewells where in private tubewells are being prohibited to be installed, would hit hard to the farmers, particularly in cases where they would not be given water from the augmentation tubewells. They suggested that this limit should be reduced from 150 meters to only 50 meters.

The Commissioner, Irrigation and Power, after consulting the Chief Engineer (Canals) assured the Committee that in such cases the Government will supply water to mitigate their hardship from the augmentation tubewells and will not allow them to suffer on this account.

Keeping in view the assurance given by the Commissioner, Irrigation and Power Department, The Committee re-drafted clause 5.

अब इस बिल में जा यह क्लॉज आई है, यह इस तरह से ड्राफ्ट की गई है और उस अ योरैन्स के साथ ड्राफ्ट की गई है। मैं आपके द्वारा सरकार से यह कहना चाहूंगा कि मंत्री महोदय

इसके बारे में यहां हाउस में आवास दे और इस चीज को जैसे भी हो इस बिल के साथ किसी ऐसे ढंग से जोड़ा जाए ताकि यह आवास बना रहे और किसान के सामने जो मुक्ति आने का डर है, वह न रहे। इसके बारे में मैम्बरों ने जो सूझाव दिए, उनके ऊपर पूरी तरह से विचार किया गया। यह क्लोज 5 कई मीटिंगों में विचार विमर्श पचात पोस्टपोन होती रही। बिल फाइनल करने के बाद फिर इसको दोबारा री-ड्राफ्ट किया गया। इसलिए यह आवश्यक है कि किसान के सामने आने वाली जो मुक्ति है, कि सरकारी ट्यूबवैल से 150 मीटर तक कोई प्राइवेट ट्यूबवैल नहीं लग सकता नहीं लग सकता, उसके बारे में सरकार की तरफ से हाउस में आवास आना चाहिए। जिस किसान के पास चार या पांच एकड़ जमीन होगी, उसको बड़ी मुक्ति आएगी। न उसको सरकारी ट्यूबवैल से पानी मिलेगा और न ही वह अपना ट्यूबवैल लगा सकेगा। जो आवास कमेटी में दिया गया है कि हम उसके लिए पानी का प्रबन्ध करें, उसको पानी मिलेगा, मैं चाहता हूँ कि यह आवास सरकार की तरफ से आन दी फ्लौर आफ दी हाउस भी दिया जाए ताकि छोटे किसानों की यह हार्डशिप खत्म हो जाए। इन भावों के साथ मैं समाप्त करना चाहता हूँ। मैंने इस बिल की कोई मुखालिफत तो करी ही नहीं है, हाँ इनता जरूर कह सकता हूँ कि कोई भी कानून अच्छा है या बुरा है जब वह अमल में आएगा, जब उसको इस्तेमाल में लाएंगे, उसके बाद ही उसका पता लगेगा। जो इस बिल पर अमल करने वाले हैं, उनके मन से यह ज्यादा ताल्लूक रखता है। अपने

दे 11 की पैदावार बढ़ाने के लिए भी यह बिल किसान से सीधा ताल्लुक रखता है इसलिए यह बहुत जरूरी है कि इस बिल को पूरे ध्यान से पास किया जाए, तभी हमारे प्रान्त का भला हो सकता है। धन्यावाद।

श्री जगजीत सिंह टिक्का (नारायणगढ़) स्पीकर साहब, चौधरी शिव राम वर्मा जी ने एक बात अभी कही है, मैं सिर्फ उसके मुतालिक ही कहूंगा। इस बिल में बाकी एरिया में तो कैनल्स का ताल्लुक है लेकिन मेरी कांसटीच्यूसी के एरिया में तो कैनल का सवाल ही पैदा नहीं होता। जो ऑगमेंटेशन के ट्यूबवैल्स हैं, उनका तो मेरे एरिये से सम्बन्ध है। मेरे एरिये में गवर्नमेंट के ट्यूबवैल भी लग रहे हैं। उनके 150 मीटर के फासले तक कोई प्राइवेट ट्यूबवैल नहीं लग सकेगा, अगर यह बात उस पर भी लागू हो जाए तो इसमें कोई एतराज वाली बात नहीं है। लेकिन ऐसा करने से थोड़ी सी, दो-तीन दिक्कत आने वाली है जो मैं यहां पर मंत्री महोदय के सामने कहना चाहता हूँ। उसमें जो कमान्डिड एरिया होता है, कई दफा तमाम का तमाम ले लिया जाता है। अब उसमें नैचुरली 150 मीटर तक का एरिया आ जाएगा, हो सकता है उससे ज्यादा भी आ जाए, कई दफा उस तमाम कमान्डिड एरिया का पानी नहीं मिलता। कभी तो ट्यूबवैल फेल हो जाता है और कई दफा कोई और कारण हो जाता है जैसे कि कोई ट्यूबवैल कम पानी देना शुरू कर दे। मिसाल के तौर पर मैंने मंत्री महोदय को यह बताया है कि ट्यूबवैल नम्बर 30

जो गहजादपुर का है, ने पानी देना बन्द कर दिया है। मंत्री महादेय ने यह वि वास दिलाया है कि किस तरह ठीक करते हैं। मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर कमान्डिट ऐरिया को पानी न मिले या किसी वजह से पानी न दिया जा सके तो फसल का बहुत नुकसान होता है। वहा पर का तकार अपना ट्यूबवैल नहीं लगा सकता। इसलिए मेरी सरकार से प्रार्थना है कि ऐसी जगहो के लिए या तो वे छूट दे कि वहा पर किसान ट्यूबवैल लगा सके या फिर कोई और प्रबन्ध किया जाए। एक दूसरी बात यह है कि सरकार जहां ट्यूबवैल लगात है वहा एम.सी.जी. ली जाती हैं। जैसे बिजली वाले एम.सी.जी. लेते हैं इसी तरह से ट्यूबवैल पर भी लेते हैं कि हम आपको इतनास पानी देंगे और आपको इतना खर्चा देना पड़ेगा। अगर उतना पानी मिल जाये और उतना देखने मे आयी है कि पानी मिलता नहीं है लेकिन एम.सी.जी. ले लेते हैं। इसका मतलब तो यह हो गया कि पानी मिले या न मिलें, का तकार को पैसे देने पड़ेगे मैंने एग्रीमेंट मे भी इसके लिए प्रोवीजन कराने की कोि। रूा की है कि इस एग्रीमेंट हो और अगर पूरा परनी न मिले तो एम.सी.जी. लागू नहीं होनी चाहिए। आपके द्वारा मंत्री जी से यही मेरी डिमान्ड है। इस वजह से लोग कतराने लग गए हैं और एम.सी.जी. नहीं देते। अगर नहीं देते तो उन पर जुर्माना हो जाता है। अगर किसान का पानी न मिले तो उससे एम.सी.जी. नहीं लेनी चाहिए। अगर किसी का एक दफा पानी मिल गया तो भी पैसे उतने ही लेते हैं और अगर किसी को पूरा पानी मिल गया तो उतने ही। इसलिए मैं मंत्री जी से प्रार्थना

करूंगा कि इस चीज पर वे गौर कर ले ताकि लोग इस दिक्कत से बच सकें।

चौधरी मेहर चन्द(बडोपल): स्पीकर साहब, इस बिल को अपोज करने का तो मेरा सवाल ही पैदा नहीं होता लेकिन कुछ ऐसी बातें इसके अन्दर हैं जो इसके अन्दर से ही ऐमर्ज होती हैं और वे मैं आपके द्वारा गवर्नमेंट के नोटिस में लाना जरूरी समझता हूँ। हाउस को पता ही है कि यह बिल सिलैक्ट कमेटी को रैफर हुआ। सिलैक्ट कमेटी ने बड़े गौर से इसको ट्रिस्मलाईन करने की कोशिश की है और जो भाउर्ट-कमिन्गज औरिजलन बिल में थी, उनको रिमूव किया है। इसके बाद एक चीज निहायत जरूरी यह आती है। कि इस बिल के रूलज के अन्दर अभी बहुत कुछ चीजे छोड़ी हैं। मैं आपके द्वारा हरियाणा सरकार से यह दरखास्त करूंगा कि रूलज के अन्दर अभी बहुत से प्रोविजन्ज होने हैं, इस वास्ते चन्द आईटम्ज ऐसी हैं जिनके ऊपर ख़ास ध्यान देना निहायत जरूरी है। मसलन डिसिट्रिब्यूशन आफ इरिगेशन स्लिप्स इस चीज को जिसके बारे में मैं कहना चाहता हूँ, मेरे सब भाई कच्ची पर्ची कहते हैं और रूलज के अन्दर इस बारे में प्रोवीजन जरूर है। मैं इस बात से डिलाई नहीं करता। हालांकि ऐग्जीस्टिंग रूलज के अन्दर इसका प्रोविजन है लेकिन ऐग्जीस्टिंग रूलज को थौरौली रिवाईज करना पड़ेगा। in the light of provisions made in the new Act now. इस वास्ते जब वह प्रोवीजन करे तब वहाँ पर एक चीज का प्रोवीजन होना निहायत

जरूरी है क्योंकि वह अभी लैक करती है जिसकी वजह से किसान बेचारे को पूरी अपरच्युनिटी नहीं मिलती है। दर हकीकत होता क्या है? यह जो कच्ची पर्ची होती है जब इसको पटवारी तकसीम करता है तो कुछ पर्चियां नम्बरदार के सुपुर्द कर देता है और कुछ खुद बांटता है। पर्चियां ऐक्चुअल तकसीम ही नहीं हकी जाती और बहरहाल जो तकसीम पर्चा होता है, वह फर्जी होता है। इसलिये मैं हरियाणा सरकार से विनती करूंगा कि जो रूलज बनाये जायें, उनमें डैटिड एकनोलेजमेंट का प्रोवीजन होना निहायत जरूरी है ताकि वह गरीब किसान उजरदार कर सके। होता क्या है? कोई किसान खेत में बोता तो चरी है लेकिन खसरे के अन्दर काटन दर्ज कर दिया जाता है। जब उजरदारी का टाईम निकल गया तो क्या वह उजरदारी काटन की दे? टाईम पर पर्ची न पहुंचने के कारण वह बेचारा उजरदारी नहीं कर सकता और बड़ी कठिनाई में फंस जाता है।

Mr. Speaker: Order please. You were a member of the Select Committee. रूलज अभी अने नहीं है। जब रूलज बनेगे तो वे हाउस के सामने आयेगे। आप तो उनका पहले ही एन्सीसिपेटरी क्रिटीसाईज कर रहे है।

चौधरी मेहर चन्द: स्पीकर साहब, कमेटी के अन्दर यह बात डिस्कस हुई थी अगर आप इजाजत नहीं देते मैं बैठ जाता हूं। मैं बिल की बाबत नहीं कह रहा हूं मैं तो रूलज के लैक्यूने

की बात कर रहा हूँ। अगर आप मुझे इजाजत नहीं देते than I resume me seat.

Mr. Speaker: Hons. Minister.

सिंचाई तथा बिजली मंत्री (श्री बनारसी दास गुप्त):
अध्यक्ष महोदय, जैसा कि अभी सदन के सामने सम्मानित सदस्यों द्वारा यह विचार व्यक्त किए गए कि यह बिल बड़ा महत्वपूर्ण है। इसमें कोई संदेह नहीं कि यह बड़ा अहम बिल है और पूरी एक सदी के पश्चात् इसमें संशोधन किया जात रहा है क्योंकि यह बिल बड्ढा महत्वपूर्ण था और खासतौर से हरियाणा की खुशहाली, विकास और किसानों से सम्बन्ध रखता था इसलिए पिछले विधान सभा के सत्र में यह बिल सिलैक्ट कमेटी के सुपुर्द किया गया। अध्यक्ष महोदय आप जब सिलैक्ट कमेटी में मैम्बरना की लिस्ट देखेंगे तो पता चलेगा कि उसमें हमारे ऐसे सम्मानित सदस्य थे जो इस विषय में पूरी दिलचस्पी रखते और समझ रखते थे। उनको इस सिलैक्ट कमेटी में भामिल किया गया और उन्होंने काफी सोच विचार और बड़े गहरे अध्ययन के पश्चात् अपनी रिपोर्ट सदन के सामने प्रस्तुत की है। जैसा कि अभी वर्मा जी ने बतलाया कि इस रिपोर्ट को तैयार करने में मैम्बरान ने बड़ी मेहनत की। मैं उन सब का बड़ा अभारी हूँ और खास तौर से वर्मा जी ने चौधरी मेहरचन्द के नाम का संकेत किया। इसमें कोई संदेह नहीं कि उन्होंने बड़ी दिलचस्पी बड़े परिश्रम के साथ अपना योगदान इस रिपोर्ट को तैयार करने में दिया है और हमारे सिंचाई विभाग के

इंजिनियर और सिंचाई और बिजली विभाग के जो आयुक्त हैं उन सब ने इस रिपोर्ट के तैयार करने में बड़ा सराहनीय काम किया है समय समय पर उन्होंने बड़े अच्छे सूझाव पदिए और डिस्कंज तथा विचार विर्म के समय पूरी तरह से इस बात की और ध्यानव दिया कि यह बिल ऐसा तैयार किया जाए कि जिससे ज्यादा से ज्यादा सुविधाए किसानों को प्रदान की जा सके और उनको अपनी जमीन में नहरों का पानी लगाने में आज जो कठिनाईयां आती हैं उन सब कठिनाईयो को दूर किया जा सके और इस बात की पूरी चेश्टा की गई है, प्रयत्न किया गया है लेकिन इसके बावजूद हमारे माननीय सदस्य चौधरी अमर सिंह ने कुछ आंकाए प्रकट की हैं। कुछ ऐसे खद गत प्रकट किए हैं कि कुछ बातों से किसान को तकलीफ हो सकती है। जहा तक तावान की बात है कि सी निर्धारित समय के अन्दर उसका फैसला हो जाना चाहिए, कुद इसपैव न की बात उन्होंने की है और उन्होंने इस बात का जिक्र किया है जैसे कि लाला गौरी भांकर ने कहा कि कई बार अपनी जिम्मवारी कम करने के लिए और अपने दोशों और अपने कमियों को छिपाने के लिए नहर के कर्मचारी ब्रीच का कट बना देते हैं मैं इस बात से इन्कार नहीं करता। सम्भव है कि इस प्रकार की बात हो जाती हो। नहर से किनारे कमजोर हो या कोई कमी हो और जिसके कारण ब्रीच हो जाता हो और अपनी खाल बचाने के लिए कट बना दिया जाता हों और इससे किसान को पेर पानी होती हो। मैं सदन के माननीय सदस्यों को यह वि वास दिलाता हूं कि

इस बात की और हम पूरा ध्यान देगे कि और हम पूरा ध्यान देगे कि इस प्रकार किसान को परे ान न किया जाए।

श्री अध्यक्ष: रूल्ज बनाते समय चौधरी मेहर चन्द को भामिल कर लीजिए।

श्री बनारसी दास गुप्त: मैजरमेंट की बात की गई हैं। यह ठीक है कि अन्दराज के समय आई.बी.सी. भायद गड़बड़ करते हो, हम इसका ध्यान रखेगें। मै अधिक डिटेल मे नही जाना चाहता क्योकि इस बिल पर बड़ी गहराई के साथ विचार किया गया है और जो आ ांकाए हमारे माननीय सदस्यो ने प्रकट की है, मै सरकार की ओर से एक ही वि वास दिलाता हूं कि हम इस बात की पूरी को ि ा करेगे कि किसान को कम से कम तकलीफ हमारे विभाग के किसी अधिकारी और कर्मचारी की ओर से हों।

एक बात श्री ि िव राम वर्मा ने कही है। इस बिल मे धारा 5 है जिसमे आगमेन्टे ान ट्यूबवैल के 150 मीटर के रेडियस मे प्राईवेट ट्यूबवैल लगाने की इजाजत नही दी गई है। इस बारे मे हमने अधिकारियों और इंजीनियरो से विचार विर्मश किया और जैसा कि उन्होने प्रोसीडिंगन्ज को पढकर बताया कि डिस्क ान के वक्त इस बात का यकीन दिलाया कि कोठ किसान जिसकी जमीन 150 मीटर के रेडियम मे आती है और उसको किसी अन्य प्रकार से ट्यूबवैल से पानी देगे ओर उस किसान को किसी प्रकार भी

पानी से वंचित नहीं रखेंगे। इसके अलावा अभी चौधरी मेहर चन्द जो इस सिलैक्ट कमेटी के मੈम्बर रहे हैं। उन्होंने रूल्ज की बात की, स्पीकर साहब, रूल्ज बनाते वक्त इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि सदन ने जो यह अकल पास किया है उसकी एक-एक धारा को अच्छी प्रकार इम्पीमेंट किया जाए और उससे किसी प्रकार की कोई तकलीफ किसान को न हों।

एक बात श्री जगजीत सिंह टिक्का ने एम. सी.जी के सम्बन्ध में कही है। एम.सी.जी. की भाँत लगाना जरूरी है लेकिन उससे किसान को जो तकलीफ होती है। मैं आपके द्वारा सदन के सम्मानित सदस्यों से प्रार्थना करूँगा कि इस बिल को सर्वसम्मति से पास किया जाए ताकि हम इसको भीघ ही इम्पलमेंट कर सकें, लागू कर सकें और किसान की जो कठिनाइयाँ हैं उनका हल कर सकें।

Mr. Speaker: Question is—

That the Haryana Canal and Drainage bill, as reported by the Select Committee, be taken into consideration.

The Motion was carried.

Mr. Speaker: The House will now take up the Bill clause by clause.

Sub-Clauses (2) & (3) of clause 1

Mr. Speaker: Question is—

That the Sub Clauses (2) & (3) clause 1 stand part of the bill.

The Motion was carried.

Voice: All the Clauses be put together.

Clauses 2 to 15

Mr. Speaker: Question is—

That the Clauses 2 to 15 1 stand part of the bill.

The Motion was carried

Clauses 16 to 38

Mr. Speaker: Question is—

That the Clauses 15 to 38 stand part of the bill.

The Motion was carried

Clauses 39 to 52

Mr. Speaker: Question is—

That the Clauses 39 to 52 stand part of the bill.

The Motion was carried

Clauses 53 to 66

Mr. Speaker: Question is—

That the Clauses 53 to 66 stand part of the bill.

The Motion was carried

Sub-Clauses (1) of clause 1

Mr. Speaker: Question is—

That Sub-Clauses (1) of clause 1 stand part of the bill.

The Motion was carried

Enacting Formula

Mr. Speaker: Question is—

That Enacting Formula be the Enacting of the bill.

The Motion was carried

Title

Mr. Speaker: Question is—

That Title be the Title of the bill.

The Motion was carried

सिंचाई तथा बिजली मंत्री (श्री बनारसी दास गुप्त):
श्रीमान मै प्रस्ताव करता हूँ:

कि प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप मे हरियाणा नहर तथा जल-निकास विधेयक पारित किया जाए।

Mr. Speaker: Motion moved—

That the Haryana Canal and Drainage Bill, as reported by the Select committee, be passed.

Mr. Speaker: Question is—

That the Haryana Canal and Drainage Bill, as reported by the Select committee, be passed.

The Motion was carried.

Home Minister (Sh. K. L. Poswal): Sir, I beg to move—

That the Assembly at its rising this day shall stand adjourned will 2.00 PM on Friday, the 26th July, 1974.

Mr. Speaker: Motion moved—

That the Assembly at its rising this day shall stand adjourned will 2.00 PM on Friday, the 26th July, 1974.

Mr. Speaker: Question is—

That the Assembly at its rising this day shall stand adjourned will 2.00 PM on Friday, the 26th July, 1974.

The Motion was carried.

Mr. Speaker: The House stands adjourned till 200 PM on 26th July, 1974.

***15.52**

(The Sabha then adjourned *till 2.00 PM on Friday, the 26th July, 1974.)